वर्ष 12 • अंक 295 • 12 पृष्ठ
• मूल्य 5 रुपये

गुरुवार 30 जनवरी 2020

कोलकाता, चंडीगढ़, **नई दिल्ली**, पटना, भोपाल, मुंबई, रायपुर और लखनऊ से प्रकाशित।

भारत का पहला संपूर्ण हिंदी आर्थिक अखबार

बिज़नेस स्टैंडर्ड

www.bshindi.com

▶▶ पृष्ठ 4

राजमार्ग ठेकों से 5 कंपनियां बाहर

राजीव जैन ▶▶ पृष्ठ 2

बजाज फाइनैंस का कर पूर्व लाभ 33 फीसदी बढ़ा

डॉलर रु. 71.30 (अपरिवर्तित) | यूरो रु. 78.40 ▼ 20 पैसे | सोना (10ग्राम) रु 40302 ▼ 191 रुपये | सेंसेक्स 41198.70 ▲ 231.80 | निफ्टी 12129.50 ▲ 73.70 | निफ्टी फ्यूचर्स 12156.80 ▲ 27.30 | ब्रेंट क्रूड 59.10 डॉलर ▼ 0.20 डॉलर

एक नज़र

चीन से भारतीयों को लाने की कवायद

चीन में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच भारत ने चीन से हुबेई प्रांत से अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए दो उड़ानों के परिचालन की इजाजत देने का अनुरोध किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पेइचिंग स्थित भारतीय दूतावास जरूरी चीजों पर काम करने के लिए चीनी अधिकारियों के संपर्क में है। इस बीच, वुहान से अपने नागरिकों को निकालने की भारत की तैयारियों के बीच चीन ने बुधवार को कहा कि यदि कोई देश अपने नागरिकों को निकालने पर जोर देता है तो सभी उचित प्रबंध किए जाएंगे और आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। उधर, इंडिगो और एयर इंडिया ने चीन की अपनी कुछ उड़ाने निलंबित करने की घोषणा की है। चीन में कोरोना वायरस की वजह से मरने वालों की संख्या बढ़कर 132 हो गई है। पृष्ठ 12

इंडिगो : गंगवाल का प्रस्ताव नामंजूर किया

इंडिगो के सह-प्रवर्तक राकेश गंगवाल द्वारा प्रस्तावित विशेष समाधान प्रस्ताव को बुधवार की विशेष आम बैठक में कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। कंपनी ने एक्सचेंज को दी जानकारी में कहा कि विशेष प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। इसके पक्ष में 48.56 प्रतिशत वोट पड़े जबकि विरोध में 51.44 प्रतिशत वोटिंग हुई। इस समाधान प्रस्ताव के लिए कम से कम 75 प्रतिशत शेयरधारकों के समर्थन की जरूरत थी, लेकिन राहुल भाटिया की इंटरग्लोब एंटरप्राइज ने इसके खिलाफ मत दिया जिससे यह प्रस्ताव विफल हो गया। भाटिया परिवार और इंटर-ग्लोब एंटरप्राइज (आईजीई) की इस एयरलाइन में 38.23 प्रतिशत हिस्सेदारी है, जबकि गंगवाल, उनकी पत्नी शोभा गंगवाल और ट्रस्ट का 36.65 प्रतिशत स्वामित्व है। पृष्ठ 3

प्रशांत किशोर और वर्मा जदयू से निष्कासित

जनता दल यूनाइटेड (जदयू) ने बुधवार को अपने उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर एवं महासचिव पवन वर्मा को पार्टी से निष्कासित कर दिया। पार्टी ने कहा कि हाल के दिनों में उनके आचरण ने यह स्पष्ट किया है कि वे पार्टी के अनुशासन का पालन नहीं करना चाहते हैं। दोनों नेता संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) को पार्टी अध्यक्ष एवं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समर्थन के कारण उनकी आलोचना करते रहे हैं।

यूरोपीय संघ ने 5जी के लिए जारी किए सख्त दिशानिर्देश

यूरोपीय संघ ने 5जी प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने के मामले में बुधवार को सख्त दिशानिर्देश जारी कर दिए। हालांकि, चीन की प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनी हुआवे पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। ईयू ने सदस्य देशों से कहा है कि सुरक्षा जोखिमों को ध्यान में रखते हुए वह 5जी उपकरण आपूर्तिकर्ताओं की गहन जांच पड़ताल करें।

कंपनियों के कारोबार समेटने के नियम अधिसूचित

सरकार ने कंपनी कानून के तहत कंपनियों के कारोबार समेटने के नियमों को अधिसूचित कर दिया है। इससे एनसीएलटी के बोझ को कम किया जा सकेगा। कंपनी मामलों के मंत्रालय ने कंपनी (कंपनी बंद करने संबंधी) नियमों-2020 को अधिसूचित कर दिया है। ये नियम 1 अप्रैल 2020 से लागू होंगे।

त्यापार गोष्ठी

कोरोना वायरस जैसे संकट से कैसे बचें?

अपनी राय पासपोर्ट साइज फोटो और पूरे पते के साथ हमें इस पते पर भेजें :

बिज़नेस स्टैंडर्ड, नेहरू हाउस, 4 बहादुरशाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली-110002 फैक्स नंबर - 011-23720201
या फिर ई-मेल करें gosthi@bsmail.in
अपने विचार आप हमें bshindi.com पर भी भेज सकते हैं

आज का सवाल

क्या टाटा एयर इंडिया के लिए बोली लगाने में होगी सक्षम

www.bshindi.com **पर राय भेजें।**
आप अपना जवाब एसएमएस भी कर सकते हैं। यदि आपका जवाब हां है तो **BSP Y** और यदि न है तो **BSP N** लिखकर **57007** पर भेजें।

पिछले सवाल का नतीजा

क्या आम बजट में अर्थव्यवस्था में सुधार के होंगे ठोस उपाय?	हां	57.89%
	नहीं	42.11%

टाटा-एयर एशिया में होगी सुलह!

गैर-प्रतिस्पर्धी मसले पर बातचीत को राजी, एयर इंडिया की बोली में यह प्रावधान बड़ी बाधा

देव चटर्जी
मुंबई, 29 जनवरी

टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी टाटा संस और मलेशिया के उद्योगपति टोनी फर्नांडिस के स्वामित्व वाली एयर एशिया आपसी विवादों को सुलझाने के लिए बातचीत कर रही है। दोनों समूहों के बीच संयुक्त उपक्रम एयर एशिया इंडिया के लिए गैर-प्रतिस्पर्धी प्रावधान को लेकर भतभेद है।

एयर एशिया बेरहद और टाटा संस तथा पूर्व साझेदार टेलेस्ट्रा ट्रेडप्लेस के बीच 19 फरवरी, 2013 में आपसी समझौते पत्र में विशिष्ट प्रावधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसके तहत सभी साझेदारों को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किफायती विमानन कारोबार में उतरने की अनुमति नहीं है। गैर-प्रतिस्पर्धी समझौते के अनुसार कोई भी साझेदार ऐसी किसी विमानन कंपनी में निवेश नहीं कर सकती हैं जो घरेलू और अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर किफायती, यात्री विमानन सेवा, नैरो बॉडी वाले विमानों के परिचालन करती हैं।

मामले के जानकार सूत्रों ने कहा कि गैर-प्रतिस्पर्धी प्रावधान एयर इंडिया के लिए बोली लगाने में टाटा के लिए बाधक बन रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एयर इंडिया के साथ उसकी सहायक इकाई एयर इंडिया एक्सप्रेस की सीधे तौर पर एयर एशिया इंडिया से प्रतिस्पर्धा है। एयर इंडिया के लिए सरकार ने 17 मार्च तक अभिरुचि पत्र जमा कराने को कहा है। एयर एशिया इंडिया में टाटा की 51 फीसदी हिस्सेदारी है और पिछले दो साल में कंपनी में अपना प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्याधिकारी नियुक्त कर संयुक्त उपक्रम पर पूर्ण नियंत्रण में ले लिया है। शेष हिस्सेदारी एयर एशिया के पास है। घटनाक्रम के जानकार एक सूत्र ने बताया, 'दोनों समूह लंबित मसलों को सुलझाने के लिए बात कर रहे हैं।'

इस बारे में पक्ष जानने के लिए टाटा संस और एयर एशिया इंडिया के प्रवक्ता से संपर्क किया गया लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। एयर एशिया बेरहद को भेजे गए ईमेल का भी कोई जवाब नहीं आया।

एन चंद्रशेखरन
चेयरमैन, टाटा संस

टोनी फर्नांडिस
सीईओ, एयर एशिया

- एयर इंडिया पर टाटा की बोली पर आपत्ति कर सकती है एयर एशिया
- एयर एशिया इंडिया में गैर-प्रतिस्पर्धी प्रावधान है विवाद की वजह
- कोई भी साझेदार किफायती विमानन कंपनी में नहीं कर सकता है निवेश
- एयर इंडिया एक्सप्रेस की वजह से टाटा एयर इंडिया के लिए बोली लगाने में सक्षम नहीं
- दोनों पक्ष सभी लंबित मुद्दे निपटाने के लिए बातचीत को तैयार

दोनों पक्षों के बीच बातचीत ऐसे समय में शुरू हो रही है जब फर्नांडिस धनशोधन के आरोपों में ईडी की जांच का सामना कर रहे हैं। ईडी ने समन जारी कर 5 फरवरी तक 2014 से विमानन कंपनी के परिचालन के बारे में पूरी जानकारी मांगी है। ईडी की जांच के अलवा फर्नांडिस आपराधिक षड्यंत्र के आरोपों में भी सीबीआई जांच का सामना कर रहे हैं। सीबीआई द्वारा मई 2018 में दायर प्रारंभिक रिपोर्ट में आरोप लगाया था कि मलेशियाई साझेदार नियंत्रित एयर एशिया इंडिया ने अप्रत्यक्ष तौर पर विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड के नियमों का उल्लंघन किया है और कंपनी के सभी अहम निर्णय खुद ले रहे हैं। आरोप है कि विमानन कंपनी ने भारत में परिचालन जल्द शुरू करने की मंजूरी के लिए लॉबीइस्ट का सहारा लिया था और इसे एयर एशिया बेरहद की स्थानीय सहायक इकाई के तौर पर परिचालन कर रही थी। हालांकि एयर एशिया ने इन आरोपों से इनकार किया है और फर्नांडिस अब तक जांच एजेंसियों के समक्ष हाजिर नहीं हुए हैं। दोनों साझेदारों के बीच पहली बार मतभेद उस समय उजागर हुए जब टाटा समूह के वकील और एयर एशिया इंडिया के बोर्ड के निदेशक भरत वसानी ने नवंबर 2014 को ईमेल भेजकर कहा था कि एयर एशिया बेरहद एयर एशिया इंडिया का परिचालन अपने एक विभाग के तौर पर कर रही है।

डीएचएफएल:12,773 करोड़ रु. का हेरफेर

श्रीमी चौधरी
नई दिल्ली, 29 जनवरी

- धीरज वधावन ने मार्च 2010 में जायदाद खरीदने के लिए मिर्ची से मिलाया हाथ
- दोनों के बीच 225 करोड़ रुपये में हुआ सौदा
- 111 करोड़ रुपये मिर्ची को डीएचएफएल, आरकेडब्ल्यू डेवलपर्स से मिली
- अतिरिक्त 154 करोड़ रुपये वधावन की दुबई की कंपनी से मिले
- रकम के स्रोत छुपाने के लिए कपिल वधावन ने सनब्लिंक का किया इस्तेमाल
- डीएचएफएल ने अपने प्रवर्तकों से कथित तौर पर जुड़ीं पांच मुखौटा कंपनियों को किया 1,500 करोड़ रुपये का भुगतान
- बाद में इन कंपनियों का सनब्लिंक के साथ हुआ विलय

कर्ज संकट से जूझ रही दीवान हाउसिंग फाइनैंस (डीएचएफएल) ने 12,773 करोड़ रुपये के ऋण अपने प्रवर्तकों से कथित तौर पर जुड़ी 90 फर्जी कंपनियों को अवैध तरीके से स्थानांतरित किए थे। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अनुसार कंपनी ने 2010 और 2015 के बीच खुदरा ऋण की आड़ में करीब 1 लाख फर्जी ग्राहकों के नाम पर इस रकम की हेराफेरी की थी। ईडी माफिया सरगना इकबाल मेनन (इकबाल मिर्ची) को रकम देने में डीएचएफएल के प्रवर्तकों की भूमिका की जांच कर रही है। ईडी ने कहा कि कपिल वधावन ने धन शोधन के जरिये इन बेजा लेनदेन में अहम भूमिका निभाई थी।

ईडी ने मिर्ची की जायदाद से जुड़े धन शोधन मामले में इस सप्ताह के शुरू में वधावन को गिरफ्तार किया था। इस जांच एजेंसी ने अपनी जांच रिपोर्ट में कहा, 'यह एक ऐसा फर्जीवाड़ा लग रहा है, जिसके व्यापक परिणाम हो सकते हैं। अब तक शुरुआती जांच में पता चला है कि 12,700 करोड़ रुपये से अधिक रकम की हेराफेरी हुई है और यह पूरी साजिश कपिल वधावन ने रची थी।' रिपोर्ट में कहा गया है कि और अधिक सबूत, दस्तावजे आदि जुटाने के लिए छापेमारी चल रही है और ऐसी आशंका है कि फर्जीवाड़ा काफी बड़ा हो सकता है।

डीएचएफएल के बहीखातों पर नजर दौड़ाने से पता चलता है कि 2,186 करोड़ रुपये (12,770 करोड़ रुपये में) पांच कंपनियों-फेथ रियल्टर्स, मार्वल टाउनशिप, एबल रियल्टी, पोजीडॉन रियल्टी और रेंडन रियल्टर्स- को दिए गए थे। ईडी ने कहा कि वधावन ने सबसे पहले डीएचएफएल से पांच मुखौटा कंपनियों को एक बड़ी रकम की हेराफेरी की और बाद में डीएचएफएल से ली गई कथित तौर पर ली गई रकम को छुपाने के लिए इन कंपनियों का विलय सनब्लिंक रियल एस्टेट के साथ कर दिया। जांच एजेंसी ने कहा कि ये पांचों कंपनियां और सनब्लिंक एक दूसरे से जुड़ी हैं रकम का स्रोत छुपाने के लिए वधावन ने इनका इस्तेमाल किया है। ये ऋण पांच से छह वर्षों (2010 से 2016) के बीच आवंटित एवं इधर से उधर किए गए। यह तब हुआ जब वधावन के भाई एवं डीएचएफएल के प्रवर्तक धीरज वधावन ने सनब्लिंक के नाम पर मुंबई के वर्ली में मिर्ची से तीन जायदाद खरीदी थी।

80 हजार कंपनियों ने लगाया सरकार को चूना

सोमेश झा
नई दिल्ली, 29 जनवरी

- सरकार को लगाई 300 करोड़ रुपये की चपत
- पीएमआरपीवाई के तहत करीब 10 लाख लाभार्थी नहीं थे हकदार
- ईपीएफओ ने वसूली 222 करोड़ रुपये की राशि

देश के करीब 80 हजार ऐसी कंपनियों का पता चला है जिन्होंने व्यवस्था का धता बताकर केंद्र सरकार को 300 करोड़ रुपये का चूना लगाया। इन कंपनियों ने संगठित क्षेत्र में नई नौकरियां पैदा करने के लिए चलाई जा रही योजना के तहत सरकार से वित्तीय प्रोत्साहन लिया।

प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) के तहत करीब दस लाख लाभार्थी ऐसे पाए गए हैं जो इसके पात्र नहीं हैं। ये लोग योजना की शुरुआत से पहले से ही संगठित अर्थव्यवस्था का हिस्सा थे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने इन कर्मचारियों के भविष्य निधि खातों में लेनदेन पर रोक लगा दी है। बिज़नेस स्टैंडर्ड द्वारा देखे गए दस्तावेजों के मुताबिक ईपीएफओ पहले ही इन कर्मचारियों से 222 करोड़ रुपये वसूल चुका है। इन दस्तावेजों में विस्तार से इस पूरे प्रकरण की जानकारी दी गई है।

इस बारे में श्रम एवं रोजगार सचिव हीरालाल समारिया और ईपीएफओ के केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त सुनील बड़थ्वाल को 13 जनवरी को भेजे गए सवालों का कोई जवाब नहीं आया। दिलचस्प बात है कि ईपीएफओ के नौकरी के आंकड़ों का हवाला देकर सरकार औपचारिक क्षेत्र में नौकरियां बढ़ने का दावा कर रही है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार ने 2016 में पीएमआरपीवाई की घोषणा की थी। इसके तहत सरकार नए कर्मचारियों की भविष्य निधि राशि का एक हिस्सा खुद वहन करती है ताकि कंपनियों के वित्तीय बोझ को साझा किया जा सके। पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2016-17 के अपने बजट भाषण में कहा था कि इस योजना का मकसद कंपनियों को बेरोजगारों को नौकरी देने और असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को संगठित क्षेत्र में लाने के लिए प्रोत्साहित करना है। यह योजना अगस्त 2016 को अस्तित्व में आई थी और यह 1 अप्रैल, 2016 से नौकरी पर रखे गए नए कर्मचारियों के लिए थी।

पीएमआरपीवाई योजना के जरिये केंद्र सरकार तीन साल तक कर्मचारी की भविष्य निधि राशि में नियोक्ता का हिस्सा देती है। अभी कर्मचारी के वेतन में से 24 फीसदी राशि पीएफ खाते में जाती है। इसमें आधा हिस्सा नियोक्ता का और आधा कर्मचारी का होता है। 15 हजार रुपये तक मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए यह अनिवार्य है। इस योजना के सबसे अहम शर्त यह है कि कंपनियों को उसी स्थिति में सरकार से वित्तीय समर्थन मिलेगा जब वे ऐसे कर्मचारी को नौकरी पर रखेंगी जो पहले ईपीएफओ योजनाओं का हिस्सा न रहा हो। अलबत्ता, 16 जुलाई 2019 तक करीब 80 हजार कंपनियों के 898,576 कर्मचारी ऐसे पाए गए जिनका पहले से ही पीएफ खाता था। यह संख्या इस योजना से लाभांवित हुए 1.21 करोड़ कर्मचारियों में से करीब 7 फीसदी है। ईपीएफओ जुलाई 2019 तक ऐसे कर्मचारियों से 222 करोड़ रुपये की राशि वसूल चुका है।

शिक्षा बजट बढ़ा मगर खर्च में पीछे

रामवीर सिंह गुर्जर
नई दिल्ली, 29 जनवरी

- बजट का 26 फीसदी हिस्सा शिक्षा को आवंटित, पिछली सरकार में यह आंकड़ा 16.6 फीसदी था
- 5 साल में एक भी बार आवंटित राशि का 80 फीसदी से ज्यादा खर्च नहीं कर पाई सरकार

दिल्ली के विधानसभा चुनाव में शिक्षा एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनकर उभरा है और बीते दो दिन से दिल्ली के सरकारी स्कूलों की हालत पर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच आरोप-प्रत्यारोप चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने बीते पांच साल में शिक्षा के बजट को काफी बढ़ाया है। सरकार अपने बजट का 26 फीसदी शिक्षा क्षेत्र के लिए आवंटित करती है। लेकिन शिक्षा क्षेत्र में कार्यक्रम/योजनाओं के लिए आवंटित धन राशि को खर्च करने में सरकार पीछे है। बीते 5 साल में एक भी साल सरकार बजट में कार्यक्रमों पर आवंटित पूरी राशि खर्च नहीं कर पाई। चुनावी साल में भी शिक्षा बजट को खर्च करने की रफ्तार काफी सुस्त है।

आम आदमी पार्टी के सत्ता में आने से पहले कांग्रेस सरकार ने वित्त वर्ष 2013-14 के बजट में सामान्य व तकनीकी शिक्षा क्षेत्र में कार्यक्रमों के लिए 1,981 करोड़ रुपये आवंटित किए थे। आप सरकार ने अपने कार्यकाल के पहले वित्त वर्ष 2015-16 में इस आवंटन को दोगुने से ज्यादा बढ़ाकर 4,475 करोड़ रुपये कर दिया। लेकिन वित्त वर्ष के अंत तक करीब 2,930 करोड़ रुपये ही खर्च कर पाई, जो आवंटन का 66 फीसदी रहा।

इसी तरह आप सरकार वित्त वर्ष 2016-17 में शिक्षा क्षेत्र में कार्यक्रमों पर आवंटित 4,543 करोड़ रुपये का 74 फीसदी, वर्ष 2017-18 में आवंटित 3,333 करोड़ रुपये का 77 फीसदी और वर्ष 2018-19 के बजट में आवंटित 5,720 करोड़ रुपये का 47 फीसदी हिस्सा ही खर्च कर सकी। चुनावी और चालू वित्त वर्ष के बजट में शिक्षा क्षेत्र में कार्यक्रमों पर आप सरकार ने अब तक सबसे अधिक 6,985 करोड़ रुपये आवंटित किए, लेकिन शुरुआती छह महीनों (अप्रैल-सितंबर)के उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक इस आवंटन का महज 34 फीसदी हिस्सा ही खर्च हुआ है।

दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया का कहना है कि भाजपा व कांग्रेस शासित राज्य लगातार शिक्षा का बजट घटा रहे हैं जबकि दिल्ली सरकार ने शिक्षा बजट 26 फीसदी कर दिया है।

घरेलू वाहन उद्योग में चीनी फर्मों की सेंधमारी

पवन लाल
मुंबई, 29 जनवरी

नई दिल्ली में आयोजित होने जा रहे वार्षिक ऑटो एक्सपो में इस बार चीन की कंपनियों का दबदबा देखने को मिलेगा। आयोजन स्थल में एक तिहाई से अधिक जगह चीन की वाहन कंपनियों ने बुक कराई है। इनमें चीन की सबसे बड़ी यूटिलिटी वाहन निर्माता कंपनी ग्रेट वॉल मोटर्स, एफएडब्ल्यू की अगुआई वाली हायमा ऑटोमोबाइल्स, चीन की सरकारी कंपनी एसएआईसी शामिल हैं।

एसएआईसी की एसयूवी एमजी-हेक्टर पहले ही भारत में बिक्री के रिकॉर्ड बना चुकी है। लेकिन चीनी वाहन कंपनियों की नजर केवल एक्सपो तक ही सीमित नहीं है।

साफ है कि चीन भारतीय वाहन बाजार में गहरी पैठ बना रहा है। उसकी मूल उपकरण निर्माता (ओईएम) कंपनियों ने हाल ही में गुजरात में जीएम का संयंत्र खरीदा है। साथ ही एलएनजी ट्रक बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बिड भी जल्दी ही भारत में अपना कारोबार शुरू करने जा रही है। उसकी इलेक्ट्रिक बस बनाने की भी योजना है। एक सूत्र ने बताया कि चेरी ऑटोमोबाइल्स भी भारत में अपना संयंत्र बनाने के लिए जमीन तलाश रही है।

सवाल यह है कि चीन की कंपनियों की अचानक भारत में दिलचस्पी कैसे बढ़ गई? ग्रेट वॉल मोटर्स के कार्यकारी निदेशक पी बालेंद्रन ने कहा कि चीन बहुत बड़ा बाजार है लेकिन अब इसमें सुस्ती आने लगी है। यही वजह है कि चीन की कंपनियों को नए बाजार की तलाश है। उन्हें भारत में अपार संभावनाएं दिख रही हैं। ग्रेट वॉल ऑटो एक्सपो में कम से कम एक दर्जन कारों का प्रदर्शन कर रही है जिनमें से आधी या उससे अधिक एसयूवी होंगी। हायमा भी एक एसयूवी का प्रदर्शन कर सकती है। एमजी के सूत्रों का कहना है कि कंपनी अपनी सफल एसयूवी कार हेक्टर के इलेक्ट्रिक संस्करण के साथ कम से कम 14 अन्य कारों का प्रदर्शन करेगी। इनमें से करीब 9 एसयूवी होंगी।

एक विश्लेषक ने कहा कि भारत में अमेरिका या यूरोप से कम प्रतिस्पर्द्धा है। (शेष पृष्ठ 2 पर)

चीन में वाहनों की बिक्री

चीन की कई कंपनियां एमजी हेक्टर जैसी सफलता को भारत में दोहराने की उम्मीद कर रही हैं

चीन में वाहनों की बिक्री में आ रही गिरावट के कारण कंपनियों को अब नए बाजार तलाशने पर मजबूर होना पड़ रहा है

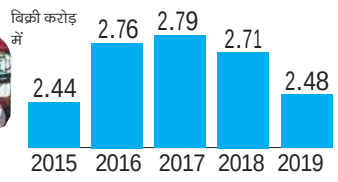

स्रोत : चाइना एसोसिएशन ऑफ ऑटोमोबाइल मैन्यूफैक्चरर्स

ऑटो एक्सपो के लिए एहतियाती कदम

चीन में कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे की वजह से 'ऑटो एक्सपो 2020' में चीन की कंपनियों की भागीदारी को लेकर चिंता बढ़ गई है। वाहन विनिर्माताओं के संगठन (सायम) ने कहा है कि स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देशों के अनुरूप ही आयोजन स्थल पर एहतियात बरती जा रही है। बुधवार को सायम के प्रतिनिधियों ने स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात कर ऑटो एक्सपो के दौरान उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा की। सायम के अध्यक्ष राजन वढेरा ने कहा, 'कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए सायम के प्रतिनिधि के तौर पर हमने बताया कि स्वास्थ्य मंत्रालय के सुझावों के अनुरूप ही ऑटो एक्सपो-दि मोटर शो के आयोजन स्थल पर पर्याप्त रूप से सतर्कता बरती जा रही है।' सायम के अधिकारियों ने स्थानीय प्रशासन और अन्य सरकारी अधिकारियों के साथ बुधवार को नई दिल्ली में ऑटो एक्सपो से जुड़ी कई दौर की बैठकें कीं। पृष्ठ 12

खबरों में रहे स्टॉक

बजाज फाइनैंस

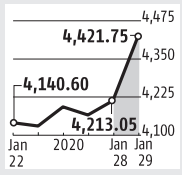

तीसरी तिमाही में मुनाफा 52 फीसदी बढ़ा

₹ 4,213.05 पिछला बंद भाव
₹ 4,421.75 आज का बंद भाव
▲ 4.59 %

आईआरसीटीसी

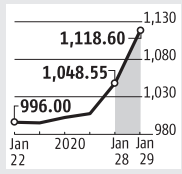

सबसे अधिक चढ़ने वाला रेल कंपनी का शेयर

₹ 1,048.55 पिछला बंद भाव
₹ 1,118.60 आज का बंद भाव
▲ 6.68 %

नारायण हृदयालय

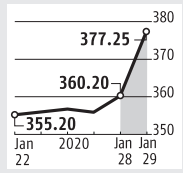

म्युचुअल फंडों ने सीडीसी ग्रुप पीएलसी से खरीदी 3.8 फीसदी हिस्सेदारी

₹ 360.20 पिछला बंद भाव
₹ 377.25 आज का बंद भाव
▲ 4.73 %

टाटा कॉफी

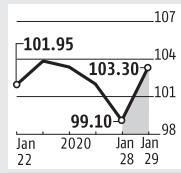

तीसरी तिमाही में कर पूर्व लाभ 70 फीसदी बढ़ा

₹ 99.10 पिछला बंद भाव
₹ 103.30 आज का बंद भाव
▲ 4.24 %

मैरिको

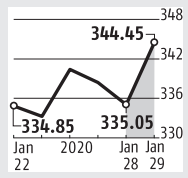

गुजरात के साणंद में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू

₹ 335.05 पिछला बंद भाव
₹ 344.45 आज का बंद भाव
▲ 2.81 %

संक्षेप में

तिमाही आंकड़े जमा करने में समय लेगी सीसीडी

कॉफी डे एंटरप्राइजेज लिमिटेड (सीडीईएल) ने आंतरिक जांच पूरी न होने के कारण बुधवार को स्टॉक एक्सचेंजों से अपनी पहली और दूसरी तिमाही की आय के आंकड़े जमा कराने के लिए अतिरिक्त समय मांगा है। पिछले वर्ष अगस्त माह में सीडीईएल ने कंपनी के संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय वी.जी. सिद्धार्थ द्वारा लिखे गए कथित पत्र की जांच करने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो के सेवानिवृत डीआईजी अशोक कुमार मल्होत्रा को नियुक्त किया था। उन्हें एक लेखा फर्म की मदद से कंपनी के खाता-बही की जांच करने का भी काम सौंपा गया था। इससे पहले दोनों स्टॉक एक्सचेंज ने सीडीईएल को चेताया था कि 29 जनवरी तक आंकड़े जमा नहीं करने की स्थिति में नियमों के उल्लंघन के तहत कंपनी के शेयरों में कारोबार पर रोक लगाई जा सकती है। *बीएस*

होंडा कार्स के ग्रेटर नोएडा संयंत्र के लिए वीआरएस

वाहन क्षेत्र की कंपनी होंडा कार्स ने अपने उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित कारखाने के कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना वीआरएस) पेश की है। कंपनी का कहना है कि वह कारखाने की उत्पादकता और दक्षता बढ़ाने के लिए यह कदम उठाने जा रही है। इस योजना पर कारखाने की श्रमिक यूनियन के साथ सहमति बन चुकी है। यह योजना 28 जनवरी से 17 फरवरी, 2020 तक खुली रहेगी। *भाषा*

डॉलर के मुकाबले रुपये में सात पैसे की मजबूती

घरेलू शेयर बाजार में तेजी आने के बाद बुधवार को अंतर बैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया सात पैसे बढ़कर 71.24 रुपये प्रति डॉलर पर पहुंच गया। *भाषा*

जुबिलैंट, वेस्टलाइफ की बिक्री में तेजी

दिसंबर तिमाही में जुबिलैंट फूडवर्क्स और वेस्टलाइफ डेवलपमेंट की बिक्री में 6 से 9 फीसदी की बढ़त

विवेट सुजन पिंटो और श्रीपद एस ऑटे
मुंबई, 29 जनवरी

देश के दो बड़े क्विक सर्विस रेस्टोरेंट (क्यूएसआर) जुबिलैंट फूडवर्क्स और वेस्टलाइफ डेवलपमेंट ने अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में जून-सितंबर तिमाही के मुकाबले अच्छी बिक्री दर्ज कराई है। कंपनियों ने ऐसे समय में सकारात्मक प्रदर्शन दर्ज कराया है जब देश के घरेलू उपभोक्ता बाजार में कमजोर रुख बना हुआ है और शोध एजेंसी नीलसन ने भी पिछले सप्ताह अपने तिमाही आंकड़ों में इसके बारे में बताया है।

डोमिनोज पिज्जा तथा डंकिन की भारत में प्रमुख फ्रेंचायजी फर्म जुबिलैंट फूडवर्क्स की तीसरी तिमाही में सेम स्टोर सेल ग्रोथ (एसएसजी) छह फीसदी रही। एसएसजी एक साल में किसी स्टोर की बिक्री में हुई वृद्धि को दर्शाती है। इसी तरह, पश्चिम तथा दक्षिण भारत में मैकडॉनल्ड्स के स्टोर चलाने वाली वेस्टलाइफ डेवलपमेंट ने एसएसजी में 9.2 फीसदी की वृद्धि दर्ज कराई। एसएसजी एक तरह से ग्राहकों की बढ़ती मांग का परिचायक होता है।

कंपनियों द्वारा जारी आंकड़े बताते हैं कि सितंबर तिमाही में दोनों कंपनियों के एसएसजी में 5 से 7 फीसदी की बढ़ोतरी हुई जबकि जून तिमाही में यह 4 से 6 फीसदी थी।

नीलसन का कहना है कि भारत में ग्राहक उपभोग क्षेत्र की वृद्धि में गिरावट आई है और यह छह तिमाहियों के सबसे निचले स्तर पर पहुंचकर 2019-20 की तीसरी तिमाही में 6.6 फीसदी पर रह गई। नीलसन के अनुसार, अगर इन आंकड़ों में ऑनलाइन बिक्री को शामिल कर लिया जाए तो ग्राहक उपभोग क्षेत्र की वृद्धि दर दिसंबर तिमाही में 7.3 फीसदी रही। शोध कंपनी का कहना है कि इस क्षेत्र के सकारात्मक आंकड़ों का असर जनवरी-मार्च तिमाही में दिखाई देगा और आगे लगातार सुधरता जाएगा।

कई विश्लेषक दिसंबर 2019 को समाप्त तिमाही के लिए इन दोनों कंपनियों की बिक्री में तेजी का अनुमान लगा रहे थे क्योंकि एक वर्ष पहले भी समान अवधि में दोनों की एसएसजी दो अंकों (वेस्टलाइफ की 14.5 फीसदी और जुबिलैंट फूडवर्क्स की 14.6 फीसदी) में थी।

आखिर तीसरी तिमाही में बिक्री में तेजी आने के प्रमुख कारण क्या रहे। वेस्टलाइफ डेवलपमेंट के उपाध्यक्ष अमित जटिया का कहना है कि दैनिक स्तर पर क्षमता सुधार, बेहतर ग्राहक अनुभव और डिजिटलीकरण अपनाने की कंपनी की रणनीति से सुधार हुआ है। वह कहते हैं, 'मैकेफी, मैकडिलिवरी और मैकब्रेकफास्ट जैसे प्लेटफॉर्म के द्वारा हमने ग्राहकों को विभिन्न विकल्प उपलब्ध कराए हैं। इससे ग्राहकों की भावनाओं के साथ जुड़ने का अवसर मिला जिसने कारोबार बढ़ाने में मदद की।'

जुबिलैंट फूडवर्क्स के अध्यक्ष श्याम भारतीय कहते हैं, 'हमने व्यापार की मूल बातों पर ध्यान दिया तथा ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने से तेज बिक्री में मदद मिली। हम इन प्रमुख कारकों पर जोर देना जारी रखेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे।'

रिलायंस सिक्योरिटीज के विश्लेषक प्रियांक छेडा कहते हैं, 'जुबिलैंट फूडवर्क्स के लिए निकट समय में वृद्धि दर्ज की गई है। हालांकि कच्चे माल की अधिक लागत के कारण मार्जिन पर दबाव बना रहेगा लेकिन कंपनी द्वारा कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना नहीं है क्योंकि यह प्रतिस्पर्धा को आकर्षित करेगा।' विशेषज्ञों का कहना है कि इन दोनों कंपनियों के लिए कुल डिलिवरी में ऑनलाइन बिक्री इस समय 85-90 फीसदी हिस्सेदारी रखती है जो एक साल पहले 70 फीसदी थी। एडलवाइज में कार्यकारी उपाध्यक्ष (शोध) अवनीश रॉय कहते हैं कि शहरी क्षेत्रों में अधिक स्टोर, गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ और कम कीमतों ने दोनों कंपनियों की बढ़ती बिक्री में अहम भूमिका निभाई।

बढ़ रही बिक्री

- दैनिक स्तर पर क्षमता सुधार, बेहतर ग्राहक अनुभव और डिजिटलीकरण अपनाने की कंपनी की रणनीति से सुधार हुआ
- कच्चे माल की अधिक लागत के कारण मार्जिन पर दबाव बना रहेगा लेकिन कंपनी द्वारा कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना नहीं
- दोनों कंपनियों के लिए कुल डिलिवरी में ऑनलाइन बिक्री इस समय 85-90 फीसदी हिस्सेदारी रखती है जो एक साल पहले 70 फीसदी थी

घरेलू वाहन उद्योग में चीनी कंपनियों की सेंधमारी

पृष्ठ 1 का शेष...

आईएचएस मार्किट के प्रधान विश्लेषक (पावरट्रेन फोरकास्ट) सूरज घोष ने कहा कि चीन को सस्ता माल बनाने में महारत हासिल है। जापान और कोरिया की कंपनियों के बाद चीन का आना सबसे गंभीर प्रयास हो सकता है।

चीनी कंपनियों के आने से घरेलू कंपनियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आज करीब 70 फीसदी भारतीय बाजार पर ए और बी श्रेणी की कारों का कब्जा है। इनमें मारुति ऑल्टो और स्विफ्ट जैसे मॉडल शामिल हैं। एसयूवी श्रेणी की वृद्धि की रफ्तार 50 फीसदी या उससे अधिक है। ऐसे में भारतीय कंपनियों का दबदबा अधिक दिन तक कायम नहीं रह सकता है।

घोष ने कहा कि चीन की कंपनियां इलेक्ट्रिक प्रौद्योगिकी, उन्नत टेलीमेटिक्स और कनेक्टिविटी से अच्छी तरह लैस हैं और उनकी कीमतें बहुत कम हैं।

ऑटोकार इंडिया पत्रिका के संपादक होरमज्द सोराबजी ने कहा कि भारतीय कार कंपनियों को चीनी कंपनियों से खतरा है। भारतीय और चीनी कंपनियों में यह फर्क है कि उन्होंने अपने उत्पादों को कई वर्षों के दौरान विकसित किया है और उन्हें आधुनिक प्रौद्योगिकी तथा उपकरणों का इस्तेमाल किया गया है।

एनआईआईटी टेक का मुनाफा बढ़ा

आईटी कंपनी एनआईआईटी टेक्नोलॉजिज ने बुधवार को कहा कि 31 दिसंबर 2019 को समाप्त तीसरी तिमाही में अपना एकीकृत मुनाफा 66.29 फीसदी बढ़कर 123.3 करोड़ रुपये हो गया। कंपनी ने प्रति शेयर पर 10 रुपये का लाभांश घोषित किया है। कंपनी ने बताया कि समीक्षाधीन अवधि में परिचालन राजस्व 11.8 फीसदी बढ़कर 1,088.2 करोड़ रुपये हो गया जो वर्ष 2018-19 की इसी तिमाही के दौरान 973.3 करोड़ रुपये रहा था। कंपनी के राजस्व में अमेरिका की बड़ी हिस्सेदारी है। *भाषा*

बजाज फाइनैंस का कर पूर्व लाभ बढ़ा

बीएस संवाददाता
मुंबई, 29 जनवरी

बजाज फाइनैंस का कर पूर्व लाभ चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में 33 फीसदी बढ़कर 2,170 करोड़ रुपये हो गया। पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में कंपनी ने 1,636 करोड़ रुपये का कर पूर्व लाभ दर्ज किया था। तिमाही के दौरान कंपनी के प्रदर्शन को शुद्ध ब्याज आय से बल मिला। दिसंबर 2019 तिमाही में कंपनी की शुद्ध ब्याज आय 42 फीसदी बढ़कर 4,537 करोड़ रुपये हो गई। जबकि कुल आय 41 फीसदी बढ़कर 7,026 करोड़ रुपये हो गई। लागत को युक्तिसंगत बनाने संबंधी कंपनी की क्षमता से भी वृद्धि को रफ्तार मिली। उदाहरण के लिए, तीसरी तिमाही के दौरान कंपनी के परिचालन खर्च बनाम एनआईआई अनुपात 33.9 फीसदी रहा जो एक साल पहले की समान अवधि में 34.9 फीसदी रहा था। इससे कंपनी की लाभप्रदता में सुधार हुआ।

बजाज फाइनैंस और उसकी सहायक इकाइयों (विशेषकर बजाज होम फाइनैंस) द्वारा ब्याज दरें कम रखने से भी मुनाफे का बल मिला। तिमाही के दौरान कंपनी का समेकित शुद्ध लाभ 52 फीसदी बढ़कर 1,614 करोड़ रुपये हो गया जो वित्त वर्ष 2019 की तीसरी तिमाही में 1,060 करोड़ रुपये रहा था। तिमाही के दौरान प्रबंधनाधीन परिसंपत्तियां (एयूएम) 35 फीसदी बढ़कर 1.45 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गईं।

उम्मीद से बेहतर वित्तीय नतीजे से उत्साहित बजाज फाइनैंस का शेयर आज 4.95 फीसदी बढ़त के साथ 4,421.75 रुपये पर बंद हुआ।

तिमाही के दौरान कंपनी की सकल गैर-निष्पादित आस्तियां (एनपीए) अनुपात 1.61 फीसदी रहा जो पिछले वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में 1.55 फीसदी रहा था। हालांकि पिछली तिमाही के मुकाबले यह लगभग स्थिर रहा जो एक सकारात्मक संकेत है।

बिड़ला कॉर्प का कर पूर्व लाभ बढ़ा

लागत को नियंत्रित करने पर लगातार ध्यान देने, क्षमता की बेहतर उपयोगिता और प्रीमियत सीमेंट की बिक्री बढ़ने से बिड़ला कॉरपोरेशन का कर पूर्व लाभ चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में 207 फीसदी बढ़कर 129 करोड़ रुपये हो गया। जबकि कमजोर मांग परिदृश्य के बावजूद कंपनी का राजस्व 10 फीसदी बढ़कर 1,715 करोड़ रुपये हो गया। पिछले वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में कंपनी का कर पूर्व लाभ 42 करोड़ रुपये रहा था जबकि शुद्ध आय 1,557 करोड़ रुपये रही थी। तिमाही के दौरान कुल मिलाकर बिक्री में 7 फीसदी की वृद्धि हुई जबकि प्रीमियम सीमेंट की मात्रात्मक बिक्री में 17 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई।

टाटा पावर का कर पूर्व लाभ 23 फीसदी घटा

बीएस संवाददता
मुंबई, 29 जनवरी

बिजली उत्पादन करने वाली निजी क्षेत्र की कंपनी टाटा पावर का समेकित कर पूर्व लाभ दिसंबर 2019 तिमाही में 23 फीसदी घटकर 349.08 करोड़ रुपये रह गया जो एक साल पहले की समान अवधि में 456.27 करोड़ रुपये रहा था।

कंपनी ने कहा कि तिमाही के दौरान मुंद्रा बिजली संयंत्र के घाटे में कमी आई। हालांकि समेकित आधार पर कंपनी का कर पश्चात मुनाफा 12 फीसदी बढ़कर 246 करोड़ रुपये हो गया जो एक साल पहले की समान अवधि में 220 करोड़ रुपये रहा था। कंपनी ने अपने बयान में कहा, 'इसकी मुख्य वजह मुंद्रा में कम नुकसान और अन्य सभी कारोबार का बेहतर प्रदर्शन रही।'

तिमाही के दौरान कंपनी की एबिटा बढ़कर 1,970 करोड़ रुपये हो गई जो एक साल पहले की समान अवधि में 1,820 करोड़ रुपये रही थी। कंपनी ने कहा कि पिछले साल की समान तिमाही में मुंबई लाइसेंस क्षेत्र के लिए हस्ताक्षरित बिजली खरीद समझौते पर 272 करोड़ रुपये के स्थगित कर लाभ के बिना एबिटा सालाना आधार पर 25 फीसदी अधिक होगी।

कंटेनर टर्मिनल बनाएगी जेएसडब्ल्यू इन्फ्रास्ट्रक्चर

अदिति दिवेकर
मुंबई, 29 जनवरी

करीब 14 अरब डॉलर के कारोबार वाले जेएसडब्ल्यू ग्रुप की इकाई जेएसडब्ल्यू इन्फ्रास्ट्रक्चर ने अपनी पहली कंटेनर टर्मिनल परियोजना के लिए न्यू मंगलूरु पोर्ट ट्रस्ट (एनएमपीटी) के साथ रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत जेएसडब्ल्यू इन्फ्रास्ट्रक्चर टर्मिनल तैयार करने के बाद अगले 30 वर्षों तक उसका परिचालन करेगी। मुंबई की कंपनी इस कंटेनर टर्मिनल के विकास पर करीब 300 करोड़ रुपये का निवेश कर रही है जिसकी क्षमता 4,00,000 टीईयू की होगी। प्रस्तावित निवेश के तहत गैर-सूचीबद्ध जेएसडब्ल्यू इन्फ्रास्ट्रक्चर बर्थ संख्या 14 पर कंटेनर एवं अन्य कार्गो के हैंडलिंग के लिए सुविधा डिजाइन, बिल्ड, फाइनैंस, ऑपरेट ऐंड ट्रांसफर (डीबीएफओटी) आधार पर तैयार करेगी। इस कंटेनर टर्मिनल के घाट की लंबाई 350 मीटर होगी और वहां 9,000 टीईयू तक के जहाज को ठहराने की व्यवस्था होगी। कंटेनर के भंडारण के लिए टर्मिनल के पास 15.5 एकड़ का भंडारण क्षेत्र भी होगा।

जेएसडब्ल्यू इन्फ्रास्ट्रक्चर के संयुक्त प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्याधिकारी अरुण माहेश्वरी के हवाले से कहा गया है, 'एनएमपीटी के साथ रियायत समझौता हमारी उस रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत हमने अगले कुछ वर्षों में 200 एमटीपीए कार्गो के हैंडलिंग की क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है। एनएमपीटी पर इस कंटेनर टर्मिनल से हमें कंटेनर श्रेणी में कदम बढ़ाने और कार्गो पोर्टफोलियो के विविधीकरण में मदद मिलेगी। हम उम्मीद करते हैं कि इस टर्मिनल का परिचालन अगले साल के मध्य तक शुरू हो जाएगा। यह एनएमपीटी और मैसूर, हसन एवं बेंगलूरु तक पूरे क्षेत्र के आर्थिक विकास में उल्लेखनीय भूमिका निभाएगा।' एनएमपीटी कर्नाटक के मंगलूरु के पनाम्बुर में सभी मौसम के अनुकूल लैगून की तरह बंदरगाह है।

इंडिगो: गंगवाल का प्रस्ताव नामंजूर किया

अरिंदम मजूमदार
नई दिल्ली, 29 जनवरी

इंडिगो के सह-प्रवर्तक राकेश गंगवाल द्वारा प्रस्तावित विशेष समाधान प्रस्ताव को बुधवार की विशेष आम बैठक (ईजीएम) में कड़े विरोध का सामना करना पड़ा।

कंपनी ने एक्सचेंज को दी जानकारी में कहा है, 'स्पेशल रिजोल्यूशन पारित नहीं हुआ, क्योंकि इसके पक्ष में 48.56 प्रतिशत वोट पड़े, जबकि विरोध में 51.44 प्रतिशत वोटिंग हुई।' इस समाधान प्रस्ताव के लिए कम से कम 75 प्रतिशत शेयरधारकों के समर्थन की जरूरत थी, लेकिन राहुल भाटिया की इंटरग्लोब एंटरप्राइज ने इसके खिलाफ मत दिया जिससे यह प्रस्ताव विफल हो गया। भाटिया परिवार और इंटर-ग्लोब एंटरप्राइज (आईजीई) की इस एयरलाइन में 38.23 प्रतिशत हिस्सेदारी है, जबकि गंगवाल, उनकी पत्नी शोभा गंगवाल और ट्रस्ट का 36.65 प्रतिशत स्वामित्व है।

कई सार्वजनिक संस्थाओं ने इस समाधान के खिलाफ मत दिया। वोटिंग में 84 प्रतिशत बड़े सार्वजनिक निवेशकों में से 51.65 प्रतिशत ने इसके विरोध में मत दिया। इंटरग्लोब एविएशन में संस्थागत निवेशकों की लगभग 21 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

वोटिंग के परिणाम के बारे में गंगवाल को भेजे गए सवाल का कोई जवाब नहीं मिला है। वह अमेरिका में हैं और उन्होंने ईजीएम में हिस्सा नहीं लिया।

सह-प्रवर्तक राकेश गंगवाल द्वारा समाधान प्रस्ताव में मुख्य शेयरधारकों द्वारा शेयरों की खरीद-बिक्री से संबंधित नियमों को नरम बनाए जाने की मांग की गई थी।

गंगवाल परिवार ने अपने नोटिस में कहा कि शेयर स्थानांतरण के प्रतिबंधात्मक क्लॉज हटाने के लिए ईजीएम जरूरी थी, जो शेयरधारक समझौते (एसएचए) के समाप्त होने के बावजूद इसमें शामिल थे। यह एसएचए भाटिया और गंगवाल के बीच किया गया था और इसकी शर्तों के अनुसार यह पिछले साल नवंबर में समाप्त (2015 में कंपनी की सूचीबद्धता के चार साल बाद) हो गया। गंगवाल की अनुपस्थिति की वजह से बुधवार को हुई ईजीएम में आशंकाओं का दौरा बरकरार रहा, क्योंकि यह बैठक उनके द्वारा बुलाई गई थी और वह स्वयं इसमें शामिल नहीं हुए।

ईजीएम में इसे लेकर चिंता देखी गई कि दो सह-प्रवर्तकों के बीच टकराव की वजह से उनके शेयरों का मूल्य प्रभावित होगा। साथ ही बैठक में नए समाधान को लेकर भी अस्पष्टता बनी रही।

पुणे से बैठक में भाग लेने आए शेयरधारक अनिल सक्सेना ने कहा, 'जब सब कुछ अच्छा चल रहा है तो ऐसे में कंपनी के किसी कानून में बदलाव लाए जाने की जरूरत नहीं है। हमें कंपनी से लाभांश मिला है। हम फिलहाल कोई बदलाव लाना नहीं चाहेंगे।'

चेयरमैन एम दामोदरन ने यह स्पष्ट कहा कि इस समाधान प्रस्ताव पर वोटिंग की जरूरत नहीं थी। इंडिगो में यह विवाद गहराने के बाद से उसका शेयर 30 प्रतिशत तक गिर चुका है।

इंडिगो में विशेष समाधान प्रस्ताव पर वोटिंग

- राहुल भाटिया की इंटरग्लोबल एंटरप्राइज ने प्रवर्तकों द्वारा शेयरों की खरीद और बिक्री के नियमों में नरमी लाए जाने के प्रस्ताव का विरोध किया
- विशेष समाधान प्रस्ताव के पक्ष में 48.56 प्रतिशत वोट पड़े, जबकि विरोध में 51.44 प्रतिशत वोटिंग हुई
- इंटरग्लोब एविएशन में संस्थागत निवेशकों की हिस्सेदारी लगभग 21 प्रतिशत, जबकि गंगवाल, उनकी पत्नी शोभा गंगवाल और ट्रस्ट का स्वामित्व 36.65 प्रतिशत है

रेलिगेयर फिनवेस्ट को सैट से राहत

बीएस संवाददाता
मुंबई, 29 जनवरी

रेलिगेयर एंटरप्राइजेज की इकाई रेलिगेयर फिनवेस्ट को पूर्ववर्ती प्रवर्तकों शिविंदर और मालविंदर सिंह से जुड़े कोष के गबन के मामले में प्रतिभूति अपील न्यायाधिकरण (सैट) से राहत मिली है।

17 अक्टूबर, 2018 के आदेश में, बाजार नियामक सेबी ने रेलिगेयर फिनवेस्ट को फोर्टिस हेल्थकेयर के लिए 200 करोड़ रुपये से ज्यादा की देनदारी के लिए जिम्मेदार बताया था। इस आदेश में सिंह बंधुओं पर उनके नियंत्रण वाली कंपनियों के जरिये रकम की कथित हेराफेरी का आरोप लगाया गया था था।

सेबी ने कहा था कि रेलिगेयर फिनवेस्ट रकम की इस हेराफेरी की लाभार्थी थी और इसलिए वह यह रकम लौटाने के लिए जिम्मेदार थी।

हालांकि, 14 मार्च 2019 के एक अन्य आदेश में सेबी के पूर्णकालिक सदस्य (डब्ल्यूटीएम) ने रेलिगेयर फिनवेस्ट को सिंह बंधुओं से जुड़ी कंपनियों के लिए ऋण के तौर पर दिए गए 200 करोड़ रुपये की वसूली करने का निर्देश दिया था।

सैट ने अपने आदेश में कहा, 'एक आदेश में यह कहा गया था कि डब्ल्यूटीएम ने अपीलकर्ता को राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया है और एक अन्य आदेश में डब्ल्यूटीएम ने अपीलकर्ता को समान कंपनियों से रकम वसूलने का निर्देश दिया था। इस तरह से, मामले पर गंभीरता से विचार किए बगैर और साक्ष्य के बिना ही विरोधाभासी आदेश जारी किए गए।'

सेबी के आदेशों के बाद, रेलिगेयर फिनवेस्ट ने यह साबित करने के लिए दस्तावेज सौंपे थे कि उसे ऋणों की अदायगी के तौर पर सिंह बंधुओं से जुड़ी कंपनियों से 200 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। कंपनी ने तर्क दिया कि उस पर रेलिगेयर हेल्थकेयर की कोई रकम बकाया नहीं है। सेबी ने रेलिगेयर फिनवेस्ट के तर्क को निराधार करार दिया था।

रेलिगेयर फिनवेस्ट (अपीलकर्ता) और सेबी (प्रतिवादी) दोनों की सुनवाई के बाद सैट ने कहा, 'हमारा मानना है कि विवादास्पद आदेशों को बरकरार नहीं रखा जा सकता।'

उसने कहा, 'अपीलकर्ता का दावा है कि उसने डब्ल्यूटीएम से जुड़ी कंपनियों से कभी भी रकम उधार नहीं ली।'

सैट ने रेलिगेयर फिनवेस्ट के तर्क की अनदेखी करने के लिए सेबी की आलोचना की। सैट ने सेबी को इसकी वजह बताने का निर्देश दिया है।

- सैट ने विरोधाभासी आदेश जारी करने के लिए सेबी की आलोचना की

ऐपल के भारतीय व्यवसाय में आ रहा सुधार

अर्णव दत्ता
नई दिल्ली, 29 जनवरी

वर्ष 2018 में भारत में अपने हैंडसेट व्यवसाय को बढ़ाने के लिए संघर्ष से जूझने के बाद कंज्यूमर टेक्नोलॉजी दिग्गज ऐपल के लिए 2019 का समापन सकारात्मक बदलाव के साथ हुआ। सितंबर तिमाही में शानदार बिक्री के बाद आईफोन, आईपैड और मैकबुक निर्माता ने दिसंबर तिमाही के दौरान मजबूत प्रदर्शन दर्ज किया है।

क्यूपरटिनो में मुख्यालय वाली इस कंपनी के मुख्य कार्याधिकारी टिम कुक ने एक निवेशक वार्ता में कहा, 'हमने अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और सिंगापुर समेत कई विकसित बाजारों में दो अंक की वृद्धि दर्ज की है और साथ ही ब्राजील, चीन, भारत, थाईलैंड और तुर्की में शानदार प्रदर्शन की मदद से उभरते बाजारों में भी दो अंक की वृद्धि में सफल रहे हैं।'

कंपनी के तिमाही नतीजों की घोषणा के बाद निवेशकों को संबोधित कर रहे कुक ने कहा कि ऐपल के आईपैड व्यवसाय (जो भारत जैसे बाजारों में सामान्यत: एक छोटा सेगमेंट है) ने पिछली तिमाही के दौरान अच्छा प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा, 'आईपैड के लिए, हमने मैक्सिको, भारत, तुर्की, पोलैंड, थाईलैंड, मलेशिया, फिलीपींस और वियतनाम जैसे प्रमुख उभरते बाजारों में वृद्धि दर्ज की है।' काउंटरपॉइंट रिसर्च के अनुमानों के अनुसार, भारत में दिसंबर तिमाही के दौरान ऐपल तेजी से बढ़ रहे ब्रांडों में से एक था। उसे अपने आईफोन एक्सआर मॉडल की कीमतों में कटौती का बड़ा लाभ मिला। इसके अलावा एक्सआर जैसे नए मॉडलों के स्थानीय तौर पर उत्पादन से भी ऐपल को कीमतें नीचे लाने में मदद मिली।

काउंटरपॉइंट ने कहा है, 'इसके अलावा, वर्ष 2019 में भारत में ऐपल के नए आईफोन (11 सीरीज) को प्रतिस्पर्धी कीमतों और शानदार रणनीति के साथ तेजी से पेश किया गया। दरअसल, नई सीरीज, खासकर आईफोन 11 को पिछले साल के आईफोन एक्सआर की तुलना में कम कीमत पर पेश किया गया। इससे कंपनी को भारत में त्योहारी सीजन और इस मॉडल के पेशकश वाली तिमाही के दौरान बिक्री बढ़ाने में मदद मिली।'

टेकआर्क में प्रमुख विश्लेषक फैजल कवूसा के अनुसार, पिछले कुछ महीनों में ऐपल की बाजार भागीदारी बढ़ी है, क्योंकि प्रतिस्पर्धी सैमसंग स्मार्टफोन बाजार में चीन की कंपनियों से पैदा हुई चुनौतियों का सामना करने में व्यस्त रही है। उन्होंने कहा, 'ऐपल की बाजार भागीदारी लक्जरी सेगमेंट (50,000 रुपये से ज्यादा कीमत के फोन) में दो-तीन प्रतिशत बढ़कर 52-53 प्रतिशत हो जाने का अनुमान है।'

- ऐपल ने अक्टूबर-दिसंबर में आईफोन बिक्री में दो अंक की वृद्धि दर्ज की
- 50 प्रतिशत बाजार भागीदारी के साथ फिर से बाजार में शीर्ष स्थान पर हुई काबिज
- नए मॉडलों के स्थानीय उत्पादन, कीमत कटौती से आईफोन एक्सआर की बिक्री बढ़ी

कर छूट में विलंब से प्रभावित होगी पीएसयू ईटीएफ की मांग!

जश कृपलानी और समी मोडक
मुंबई, 29 जनवरी

सरकार की विनिवेश योजनाओं में बड़ा योगदान देने वाले पीएसयू एक्सचेंज-ट्रेडेड फंडों (ईटीएफ) को वित्त वर्ष 2020 के बजट में प्रस्तावित कर लाभ मिलना बाकी है, भले ही केंद्र ने इस विकल्प के जरिये अन्य शेयर बिक्री की तैयारी कर ली है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पहले बजट के प्रमुख प्रस्तावों में धारा 80सी के कर लाभ के दायरे में पीएसयू ईटीएफ को भी लाना शामिल है। हालांकि इस प्रस्ताव को अभी अधिसूचित किया जाना बाकी है।

उद्योग के जानकारों का कहना है कि इससे मांग प्रभावित हो सकती है, क्योंकि सरकारी ईटीएफ की ताजा पेशकश को ऐसे समय में लाया जा रहा है जब छोटे निवेशकों ने कर-बचत योजनाओं के लिए पैसा सुरक्षित रखा है।

प्लान रुपी इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के संस्थापक अमोल जोशी ने कहा, 'यदि पीएसयू ईटीएफ को कर बचत का अतिरिक्त लाभ मिले तो वे वित्त वर्ष के इस समय के आसपास धारा 80सी के तहत कर बचत विकल्पों की संभावना तलाशने वाले निवेशकों से अच्छी मांग देख सकते हैं।'

एक फंड हाउस के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'कर लाभ के अभाव में, सरकार इस अवसर को भुनाने में सक्षम नहीं होगी।'सीपीएसई ईटीएफ की सातवीं पेशकश गुरुवार को होगी, जिसका मकसद कम से कम 10,000 करोड़ रुपये की पूंजी जुटाना है।

निवेशक आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत कुल सकल राजस्व से 150,000 रुपये तक की कर छूट का दावा कर सकते हैं। इक्विटी-आधारित बचत योजनाएं (ईएलएसएस) इस कर बचत विकल्प की तलाश कर रहे म्युचुअल फंड निवेशकों के बीच लोकप्रिय हैं।

उद्योग के कारोबारियों का कहना है कि लॉक-इन पीरियड के लिए विकल्प मुहैया कराने जैसी समस्याओं से इसकी पेशकश में विलंब हुआ है। उनका कहना है कि आगामी बजट में इसे लेकर और अधिक स्पष्टता की उम्मीद की जा सकती है। 2020-2021 का बजट इस शनिवार को पेश किया जाएगा।

निवेश बैंकरों के अनुसार, ईटीएफ पर कर रियायत से सरकार को अपने विनिवेश लक्ष्य में सुधार लाने में मदद मिल सकती है। एक बैंकर ने कहा, 'सरकार को अपना विनिवेश लक्ष्य पूरा करने में समस्या का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इस वित्त वर्ष में बड़े आकार की बिक्री की संभावना नहीं दिख रही है। यदि सरकार कर लाभ के जरिये पेशकश को आसान बनाती है तो ईटीएफ से ज्यादा पूंजी आ सकती है।'

2019-2020 के लिए सरकार का विनिवेश लक्ष्य 1.05 लाख करोड़ रुपये है। अब तक सरकार ने इस वित्त वर्ष में विनिवेश के जरिये 18,094 करोड़ रुपये जुटाए हैं, जो कुल लक्ष्य का महज 17 प्रतिशत है।

पिछले वित्त वर्ष (2018-2019) में ईटीएफ ने अहम योगदान दिया, क्योंकि सरकार ने इस विकल्प के जरिये अपने कुल विनिवेश लक्ष्य का 56 प्रतिशत (45,079 करोड़ रुपये) हासिल किया।

एक फंड प्रबंधक के अनुसार, खुदरा पूंजी प्रवाह बढ़ने से फंड हाउसों को पीएसयू ईटीएफ के प्रबंधन में भी मदद मिलेगी। एक फंड प्रबंधक ने कहा, 'पीएसयू ईटीएफ उन संस्थागत निवेशकों और अमीर निवेशकों को आकर्षित करते हैं जो अक्सर निर्गम कीमत पर मिलने वाले डिस्काउंट का लाभ उठाने के लिए छोटे समय के लिए पैसा लगाते हैं।'

पिछले समय में, बड़े निवेशकों द्वारा ज्यादा रिडम्पशन से पीएसयू ईटीएफ की प्रबंधन अधीन परिसंपत्तियों (एयूएम) में कमी को बढ़ावा मिला।

सीपीएसई ईटीएफ (निप्पॉन इंडिया एमएफ द्वारा प्रबंधित) के अलावा, मौजूदा समय में भारत 22 ईटीएफ (आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एमएफ द्वारा प्रबंधित) भी मौजूद है। सीपीएसई ईटीएफ की एयूएम 31 दिसंबर 2019 तक 10,459.53 करोड़ रुपये दर्ज की गई थीं, जबकि भारत 22 ईटीएफ के लिए यह आंकड़ा 8,136.16 करोड़ रुपये था।

- केंद्र द्वारा ऐसे फंडों के लिए धारा 80सी के कर लाभ को अधिसूचित किया जाना बाकी है

नैसकॉम और जापान कर रहे मिलकर काम

नेहा अलावधी
नई दिल्ली, 29 जनवरी

जापान के रणनीतिक साझेदारों और उद्यमी पूंजीपतियों से संपर्क रखने वाले स्टार्टअप तथा प्रौद्योगिकी कंपनियों के लिए औद्योगिक संगठन नैशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर ऐंड सर्विसेज कंपनीज (नैसकॉम) और जापान एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गनाइजेशन (जेट्रो) एकजुट होकर काम कर रहे हैं। अपना बाजार दायरा और विस्तृत करने के प्रयास में नैसकॉम ने भारत और जापान की कंपनियों के बीच संपर्क सुविधा देने की दिशा में कदम बढ़ाया है। तीन स्टार्टअप पहले ही सितंबर, 2019 में आयोजित बातचीत के पहले दौर में धन प्राप्त कर चुके हैं।

देश में अधिक निवेश लाने की जापान सरकार की पहल के तहत जेट्रो भारत में जापान के लिए अधिक कारोबारी अवसर सृजित करने और उनकी पहचान करने का लक्ष्य लेकर चल रहा है।

6 राज्यों के कर राजस्व में गिरावट

दिलाशा सेठ
नई दिल्ली, 29 जनवरी

आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, मणिपुर और उत्तराखंड में चालू वित्त वर्ष के शुरुआती 8 महीनों में पिछले साल की समान अवधि की तुलना में कुल कर प्राप्तियों में गिरावट आई है।

वहीं दूसरी तरफ इस अवधि के दौरान पश्चिम बंगाल में कर राजस्व 13.44 प्रतिशत बढ़ा है।

राज्यों के राजस्व का बड़ा हिस्सा केंद्र के बंटवारे वाले कर मद, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी), पेट्रोलियम पर मूल्यवर्धित कर और शराब पर उत्पाद कर से आता है।

आंध्र प्रदेश में इस मद से आने वाला कर राजस्व 11.40 प्रतिशत गिरा है, जबकि पंजाब में 10.40 प्रतिशत की कमी आई है। इन दो राज्यों के दिसंबर तक के आंकड़े भी मौजूद हैं।

अगर आंकड़ों को देखें तो केरल में गिरावट 10.90 प्रतिशत रही है। अन्य राज्यों में मणिपुर में कर राजस्व में अप्रैल से नवंबर 2019 के दौरान 11.40 प्रतिशत कम हुआ है। गुजरात में इन कर राजस्वों में 3.11 प्रतिशत गिरावट आई है, जबकि अन्य औद्योगिक राज्य महाराष्ट्र में वित्त वर्ष 2020 के पहले 8 महीने में 0.30 प्रतिशत गिरावट आई है। बहरहाल महाराष्ट्र में दिसंबर महीने में कर प्राप्तियां बढ़ी हैं, जिससे चालू वित्त वर्ष के पहले 9 महीने में राज्य की कर प्राप्तियों में 2.87 प्रतिशत बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

उत्तराखंड में वित्त वर्ष 2020 के अप्रैल-नवंबर के दौरान कर प्राप्तियों में 0.35 प्रतिशत की गिरावट आई है।

डेलॉयट इंडिया में पार्टनर एमएस मणि ने कहा, 'राज्यों से उम्मीद की जाती है कि वह अनुपालन बढ़ाएं और जीएसटी संग्रह बढ़ाने के लिए कर चोरी की पहचान करें। इसके अलावा उन्हें वैट राजस्व बढ़ाने पर भी ध्यान देना होगा, जो पेट्रोलियम उत्पादों व अल्कोहलिक बेवरिज (शराब) से मिलता है।' इन राज्यों मे कर राजस्व में गिरावट का असर उनके राजकोषीय घाटे के आंकड़े पर पड़ रहा है। आंध्र प्रदेश में चालू वित्त वर्ष के दिसंबर महीने तक का घाटा राज्य के बजट अनुमान के 83.4 प्रतिशत पर पहुंच गया है।

इसी तरह से पंजाब में घाटा वित्त वर्ष के पहले 9 महीने में 42.4 प्रतिशत पर पहुंच गया है।

बहरहाल गुजरात में राजकोषीय घाटा चालू वित्त वर्ष के पहले 8 महीने में बजट अनुमान का 27.5 प्रतिशत रहा है। इसी तरह चालू वित्त वर्ष के पहले 9 महीने में महाराष्ट्र का राजकोषीय घाटा बजट अनुमान का 7.39 प्रतिशत रहा है।

उत्तराखंड के राजकोषीय घाटे का आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। मणिपुर में अप्रैल-नवंबर 2019 में घाटा बजट अनुमान का 3.139 प्रतिशत रहा है। पश्चिम बंगार में साल के पहले 8 महीने में घाटा बजट अनुमान का 43.7 प्रतिशत रहा है। राज्यों को अनुमति दी गई है कि वे बाजार उधारी लें, जिसे कि उनका राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत के ऊपर न जाए।

अप्रैल-नवंबर में कर राजस्व में बढ़ोतरी (प्रतिशत में)

राज्य	2017-18	2018-19	2019-20
आंध्र प्रदेश	4.80	24.20	11.40
गुजरात	13.60	16.0	-3.11
महाराष्ट्र	23.10	13.60	-0.30
पंजाब	5.30	12.40	-10.40
उत्तराखंड	0.40	16.22	-0.35
मणिपुर	-5.90	29.80	-11.40
पश्चिम बंगाल	10.01	19.90	13.44

स्रोतः सरकार

कुल मिलाकर राज्यों का घाटा रह सकता है 3 प्रतिशत : इंडिया रेटिंग

इंडिया रेटिंग्स ऐंड रिसर्च को उम्मीद है कि चालू वित्त वर्ष में राज्यों का कुल मिलाकर राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत रहेगा, जबकि बजट लक्ष्य 2.6 प्रतिशत है। अपने नोट में एजेंसी ने राज्यों के वित्त का परिदृश्य बदलकर स्थिर-से-नकारात्मक कर दिया है, चो चालू वित्त वर्ष के लिए पहले स्थिर रखा गया था।

स्थिर-से नकारात्मक को स्पष्ट करते हुए इंडिया रेटिंग के प्रमुख अर्थशास्त्री देवेंद्र पंत ने कहा कि जहां बड़े राज्य राजकोषीय झटकों के प्रबंधन में ज्यादा कारगर होते हैं, वहीं जिन राज्यों का राजकोषीय घाटा 4 प्रतिशत या ज्यादा होगी, उनकी वित्तीय स्थिति में गिरावट देखी जा सकती है। *बीएस*

बजट गतिविधियों में असम शीर्ष पर

बजट बनाने में बेहतरीन प्रथाओं का पालन करने के मामले में असम पहले स्थान पर है। ट्रांसपैरेंसी इंटरनैशनल के एक सर्वे के मुताबिक असम के बाद ओडिशा और आंध्र प्रदेश आते हैं। यह सर्वे 4 मानकों के आधार पर किया गया- सार्वजनिक खुलासे, बजट की प्रक्रिया, बजट के बाद वित्तीय प्रबंधन और बजट को ज्यादा पारदर्शी व नागरिकों के प्रति मित्रवत बनाने की कवायद। निचला स्थान पाने वाले राज्यों में गोवा, महाराष्ट्र और पंजाब का स्थान है।

ट्रांसपैरेंसी इंटरनैशनल ने कहा है कि भारत 'राज्यों का संघ' है, लेकिन भारत में राज्यों के बजट को कभी उतना महत्त्व नहीं मिला, जिसना केंद्रीय बजट को मिलता है। इसने कहा है कि इसकी वजह से राज्यों के बजट न तो समावेशी हैं, न पारदर्शी और यह देश के लिए और खासकर उस राज्य के लिए अच्छा नहीं है। एजेंसियां

ब्रेग्जिट के प्रभावी होने से निर्यातकों में जगी उम्मीद

शुभायन चक्रवर्ती
नई दिल्ली, 29 जनवरी

यूरोपीय संघ (ईयू) से ब्रिटेन के बाहर होने के बाद भारतीय निर्यातकों में दोनों देशों के बीच व्यापार संबंध बनने से फायदे की उम्मीद जगी है।

जनमत संग्रह के साढ़े तीन वर्ष बाद ब्रिटेन के दर्जे में होने जा रहे बदलाव से कारोबार करने के तरीके में महत्त्वपूर्ण बदलाव दिखाई पड़ेंगे। लेकिन निर्यातक और विशेषकर सेवाओं के निर्यातक इस अवसर का विश्लेषण कर रहे हैं।

भारतीय निर्यातक संगठनों के महासंघ के महानिदेशक ने कहा, 'निर्यात को लेकर बहुत सारी बातें ब्रिटेन और ईयू के बीच हुए समझौता शर्तों पर निर्भर करेगा। यदि ब्रिटेन यूरोपीय संघ के साथ कस्टम यूनियन में शामिल होता है तो निर्यात बिना किसी रुकावट के पहले की तरह ही जारी रहेगा और इसके लिए लॉजिस्टिक्स मूल्य श्रृंखला में बहुत अधिक बदलाव करने की जरूरत नहीं होगी।' कस्टम यूनियन सामान्य तौर पर एक व्यापार समूह होता है जिसके देशों के बीच मुक्त व्यापार होता है और उत्पादों तथा सेवाओं पर साझा बाहरी शुल्क प्रभावी होता है। इसके लिए दोनों पक्षों के बीच एक नए व्यापार समझौते की जरूरत होगी जिससे एक साझा बाह्य व्यापार नीति तैयार होगी। यह मौजूदा परिदृश्य के समान ही होगा जहां यूरोपीय संघ के सदस्य राज्य यूरोपीय आयोग के पास अधिकारी भेजते हैं जो साझा वाणिज्यिक नीति के जरिये अपने बाह्य व्यापार संबंधों के मसले पर सौदेबाजी करते हैं।

लेकिन विशेषज्ञों की नजर में इसकी गुंजाइश कम ही है। ब्रिटिश उच्चायोग में उच्च पदस्थ सूत्र ने कहा, 'ब्रिटेन की सरकार ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि वह ब्रसेल्स (यूरोपीय संघ की राजधानी) को विदेशी व्यापार के मामलों में निर्णय लेने की शक्ति नहीं सौंपेगी। ब्रेग्जिट के बाद ब्रिटेन अपने स्तर से विभिन्न देशों के साथ अपने व्यापार समझौतों पर चर्चा करेगा जिसमें वह अपने हितों का ख्याल रखेगा।' सहाय ने कहा, 'इस मुहाने पर इसका कोई मतलब नहीं है कि ब्रेग्जिट के बाद की स्थिति कैसी है।'

राजमार्ग ठेकों से बाहर 5 कंपनियां

मेघा मनचंदा
नई दिल्ली, 29 जनवरी

ऑरिएंटल स्ट्रक्चर इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड, चेतक एंटरप्राइजेज लिमिटेड, केएनआर कंस्ट्रक्शंस, सद्भाव इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, आईआरबी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड - मॉडर्न रोड मेकर्स प्राइवेट लिमिटेड (संयुक्त उद्यम) उन कंपनियों में शामिल हैं जो ठेका से बाहर निकल गए हैं।

यह निर्णय उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से परियोजना का कार्यन्वयन शुरू करने की आधिकारिक मंजूरी मिलने में देरी होने के कारण लिया है। नियमों के मुताबिक एनएचएआई काम शुरू करन के लिए सड़क डेवलपर को एक आधिकारिक तारीख देता है लेकिन ज्यादातर मामलों में भूमि अधिग्रहण में देरी होने के कारण प्राधिकरण यह तारीख दे पाने में नाकाम रहा।

पता चला है कि पांच कंपनियों ने विभिन्न राज्यों की आठ परियोजनाएं लौटा दी हैं।

इक्रा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और समूह प्रमुख शुभम जैन ने कहा, 'एचएएम परियोजनाओं के लिए निर्माण कार्य शुरू करने की तारीख देने में नजर आई देरी मोटे तौर पर भूमि अधिग्रहण की वजह से है।

भूमि अधिग्रहण की लागत बढ़ने से प्राधिकरण को भूमि अधिग्रहण करने में देरी का सामना करना पड़ रहा है लिहाजा परियोजनाओं पर असर पड़ रहा है।

31 दिसंबर, 2019 के मुताबिक वित्त वर्ष 2018 में आवंटित की गई परियोजनाओं में से 4 फीसदी परियोजनाओं और वित्त वर्ष 2019 में आवंटित की गई परियोजनाओं में से 95 फीसदी परियोजनाओं को अब तक कार्य शुरू करने की तारीख नहीं मिली है।'

अनुमानों के मुताबिक 2016-17 में भूमि अधिग्रहण की लागत करीब 1.3 करोड़ रुपये प्रति हेक्टेयर थी जो फिलहाल 3.2 करोड़ रुपये प्रति हेक्टेयर हो चुकी है।

सड़क क्षेत्र के लिए भूमि अधिग्रहण की उच्च लागत हमेशा से एक चिंता की बात रही है।

जब सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 2016 में एक्सप्रेसवे परियोजनाओं को पूरा करने की योजनाओं की घोषणा की तब विशेषज्ञों ने कहा था कि भूमि अधिग्रहण की लागत अत्यधिक होने के कारण यह इस परियोजना के लिए एक वास्तविक चुनौती होगी।

परिभाषा के मुताबिक एक्सप्रेसवे नई परियोजनाएं हैं और उसके लिए भूमि अधिग्रहण की लागत काफी अधिक है।

अनुमानों में नजर आता है कि एक्सप्रेसवे परियोजना की कुल लागत में भूमि अधिग्रहण की लागत करीब 50 फीसदी है। भूमि अधिग्रहण की लागत में राज्य दर राज्य अंतर आता है और कई बार एक ही राज्य के दो स्थानों पर लागत में अंतर आ जाता है। नई दिल्ली से कटरा (जम्मू और कश्मीर) के लिए प्रस्तावित एक्सप्रेसवे को एक सीध में बनाया जाएगा।

इससे हरियाणा में जिंद इससे बाहर रह जाएगा और यह मार्ग नई दिल्ली को पंजाब में बरनाला के रास्ते अमृतसर से जोड़ेगा। इससे नई दिल्ली से अमृतसर के बीच के यात्रा समय में करीब ढाई घंटे की कमी आएगी। इस परियोजना पर 60,000 करोड़ रुपये की लागत आएगी।

इस परियोजना पर 60,000 करोड़ रुपये की लागत आएगी और इससे दिल्ली और कटरा के बीच की दूरी में 110 किलोमीटर की कमी आएगी।

राष्ट्रीय राजमार्ग-1 के रास्ते दिल्ली से कटरा के बीच की दूरी 729 किलोमीटर है।

नई एक्सप्रेसवे परियोजनाओं का लाभ उठाएं उद्योग : गडकरी

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने उद्योग जगत से कहा है कि वह 22 नई बनने वाली एक्सप्रेस राजमार्ग परियोजनाओं के क्षेत्र में उपलब्ध व्यापक संभावनाओं का लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से वैकल्पिक ईंधन, इलेक्ट्रिक हाइवे और चार्जिंग स्टेशनों जैसे क्षेत्रों में काफी संभावनाएं हैं, जिनका उद्योग लाभ उठा सकता है। उद्योग मंडल फिक्की द्वारा आयोजित सम्मेलन परिवहन के लिए भविष्य के ईंधन को बुधवार को संबोधित करते हुए गडकरी ने विशेष रूप से एक लाख करोड़ रुपए की दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस राजमार्ग परियोजना का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं में एलएनजी स्टेशन, इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन या पेट्रोल पंप लगाने की इच्छुक कंपनियों को फायदा हो सकता है। मंत्री ने कहा, हम दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस हाइवे सहित 22 नए एक्सप्रेस हाइवे का निर्माण कर रहे हैं। इन 22 में से सात परियोजनाओं पर काम शुरू हो गया है और उद्योग के पास इनमें काफी अवसर हैं। यदि कंपनियां इसके लिए आगे आती हैं तो हम उनको राह दिखा सकते हैं। *भाषा*

बीएस सूडोकू 3651

3		1		8		7	9	
	2		7			1	4	
		7	1	9		3	8	
7			8	4	2			
		2	6	7	1	4		
			5	3	9			8
	7	9		5	6	8		
	8	5			7		2	
	3	6		2		9		7

परिणाम संख्या **3650**

7	2	9	8	6	5	1	3	4
8	3	1	7	4	9	6	2	5
6	4	5	1	2	3	9	8	7
1	7	3	9	8	4	2	5	6
5	8	4	6	1	2	3	7	9
9	6	2	5	3	7	8	4	1
4	5	8	3	9	1	7	6	2
3	9	7	2	5	6	4	1	8
2	1	6	4	7	8	5	9	3

कैसे खेलें?
हर रो, कॉलम और 3 बाई 3 के बॉक्स में एक से लेकर नौ तक की संख्या भरें।

बहुत आसान
★☆☆☆☆

क्षेत्रीय मंडियों के भाव

उत्तर प्रदेश | राजस्थान | पंजाब

कानपुर
गेहूं लूज 2000/2010, जौ 1760/1780, चावल मसूरी 2250/2300, चावल मोटा 2200/2250, सरसों 4250/4300, तिल सफेद 8700/8800, सोया (टीन) 1500/1525, तेल सरसों कच्ची घानी वैट पेड (टीन)1450/1550,

लखनऊ
गेहूं दड़ा 2000/2010, गेहूं शरबती 2850/2950, चावल शरबती सेला 3750/3800, स्टीम 4300/4400, लालमती 3200/3250, चावल (सोना) 2800/2850,

चंदौसी
(प्रति किलो): मैन्था ऑयल 1375, बोल्ड क्रिस्टल (12 नं.)1448, फ्लैक 1400, डीएमओ 985, टरपीन लैस बोल्ड 1458

मुजफ्फरनगर
गुड़ (40 किलो): लड्डू 1125/1225, खुरपा 1030/1060,चाकू 1040/1100, रसकट 920/925, शक्कर 1200/1225, चीनी मिल डिली. (क्विं.) (जीएसटी अतिरिक्त): खतौली 3315, सिहोरा 3300, बुंदकी 3260, बुढ़ाना 3325,

हापुड़
गुड़-चीनी: चीनी हाजिर 3500/3600, गुड़ (प्रति 40 किलो) बाल्टी 990/1000, तिलहन: सरसों (42 प्रतिशत कंडी.) 4275, खल: सरसों 2100/2150, बिनौला 2250/2400, चना छिलका 2100/2150,

जयपुर
अनाज: चावल डीबी 5200/5300, गेहूं (मिल) 2080/2100, मक्की 2125/2130, बाजरा 1800/1810, जौ 1800/1825, ग्वार लूज 3750/3800, ज्वार कैटलफीड 2400/2500, तेल-तिलहन: सरसों(मिल पहुंच) 4440/4450,

श्रीगंगानगर
गेहूं (ढेरी) 2000/2100, ग्वार 3700/3750, जौ 2100/2125,

जोधपुर
गेहूं 2050/2100, जौ 1800/1825, पोपकोन मक्की 4400/4500, ग्वार डिलीवरी (ऑलपेड) 4050/4100, ग्वारगम 7200/7300, बाजरा (गुजरात) 1800/1825, बाजरा (जयपुर) 1825/1835, चना 4100/4200, काबली चना 5000/6000, मूंग 7000/7200,

खन्ना
जीएसटी अतिरिक्त (प्रति क्विं.): राइसब्रान (खाद्य)(प्रति प्वाइंट)120, राइसब्रान (अखाद्य) 118, खल सरसों 1900, डीओसी: राइसब्रान बैच सफेद 1100, लाल 1100, कंटीन्यूअस 1200,

लुधियाना
दाल-दलहन: राजमां चित्रा 7800/8500, अरहर दाल 7500/8000, उड़द साबुत 7400/8400, उड़द धोया 9000/9800, छिलका 8700/9300, दाल मसूर 5900/6200, चनादाल 5400/5500,

अमृतसर
चावल: बासमती (1121 नं.) स्टीम 5900/6000, सेला 5400/5425, शरबती साधारण सेला 3700/3750, शरबती स्टीम 4100/4150, चावल 1509 सेला 5050/5100, धान: शरबती 2050/2100,

बठिंडा
रुई (प्रति मन): जे-34 पंजाब 4075/4110, हरियाणा 4050/4070, राजस्थान 4000/4070, खल (प्रति क्विं.): बिनौला 2350/2450, सरसों खल 2040/2050,

फाजिल्का
गेहूं 2020/2030, सरसों 4200/4250 रुई (प्रति मन): (जे-34) 4100/4130, कपास देशी 5100/5200, कपास नरमा (क्विं.) 5200/5300, बिनौला (टैक्सपेड): खल 2400/2500,

जालंधर
गेहूं दड़ा 2000/2040, चावल परमल कच्चा 2350/2400, से ला 2300/2350, मक्की यूपी 2100/2120, दाल उड़द छिलका 8600/9700, चना देशी 4700/4750, दाल चना 5100/5150, काबली चना 5200/6100, राजमां चित्रा पुणे 7100/8500, चीन 8100/8600,

करनाल
गेहूं दड़ा 2000/2025, बासमती चावल 6300/6400, धान 1121 नं. 2875/2900, पूसा 1509 धान 2700/2750, शरबती धान 2100/2150, सेला (1509 नं.) चावल 5050/5100, स्टीम 5900/6000,

हिसार
ग्वार 3750/3800, जौ 1840/1850, सरसों 3950/4000, मूंग 7000/7100, गेहूं 2050/2065,

जींद
जीएसटी अतिरिक्त: गेहूं 2100/2130, आटा (प्रति 44 किलो) 1040/1060, मैदा 1160/1180, देशी घी (एक ली/जार) 380/500, रिफाइंड (टीन) 1500/1550,

भिवानी
जीएसटी अतिरिक्त: सरसों 3950/4000, खल बिनौला मोटी 2200/2300, बिनौला 2600/3200, सरसों तेल 8850/8900, गेहूं 2000/2100, ग्वार 3750/3800, बाजरा 1700/1750 *एनएनएस*

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 295

कराधान की समस्या

आम बजट करीब है और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से संबंधित चिंताएं नीति निर्माताओं और निवेशकों दोनों के दिमाग में होंगी। जीएसटी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरा है और सरकार में शामिल कुछ लोग इसका दोष व्यापक पैमाने पर हो रही कर वंचना को देते हैं। खास चिंता यह है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट की सुविधा का दुरुपयोग हो रहा है। ऐसा वस्तुओं और सेवाओं की वास्तविक आपूर्ति के अभाव में इनवॉइस के दुरुपयोग के कारण हो रहा है। मौजूदा जीएसटी अधिनियम के अधीन यह एक अपराध है। दिक्कत यह है कि जीएसटी आयुक्तों को इन मामलों में गिरफ्तार करने का अधिकार भी दिया गया है। अदालतों ने इस तरह की जाने वाली गिरफ्तारियों की प्रक्रिया को लेकर विरोधाभासी निर्देश दिए हैं। यह विधायी स्पष्टीकरण के लिए उचित मामला है।

ऐसे मामलों में एक बुनियादी सिद्धांत यह है कि किसी अधिकारी को गिरफ्तारी का अधिकार केवल इसलिए नहीं सौंपा जाना चाहिए क्योंकि इससे सरकार को अधिक राजस्व जुटाने में मदद मिल सकती है। न्याय के प्रश्नों पर भी विचार किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए समुचित आकलन के बिना कोई गिरफ्तारी नहीं की जानी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने सन 2019 में कहा था कि अभियोजन तभी शुरू किया जाना चाहिए जब निर्णय प्रक्रिया पूरी हो चुकी हो। इसके अलावा अभियोजन और गिरफ्तारी पर तभी विचार किया जाना चाहिए जब अन्य उपाय नाकाम रहे हों। मसलन ब्याज और जुर्माने का भुगतान या कुछ अन्य तरह की वसूली। कर अधिकारियों को गिरफ्तारी का अधिकार प्रदान करने का सरकार का रुख निरंतरता से रहित और अस्पष्ट रहा है।

उदाहरण के लिए यदि संग्रहीत जीएसटी जमा करने में विफलता को गिरफ्तारी का आधार माना जाए तो इसके साथ टीडीएस जमा करने में नाकामी से अलग व्यवहार क्यों किया जाता है? जीएसटी के अधीन अपराधों को अन्य अप्रत्यक्ष करों से अलग क्यों समझा जा रहा है?

अधिकारियों को गिरफ्तार करने का अधिकार नफा-नुकसान का पूरा आकलन करने के बाद देना चाहिए। ऐसा कोई विश्लेषण सार्वजनिक चर्चा में नहीं आया है। यद्यपि इनपुट क्रेडिट धोखाधड़ी में गिरफ्तारी के मामले लगातार बढ़े हैं। नई जीएसटी व्यवस्था में करदाताओं को पर्याप्त बचाव मुहैया नहीं कराए गए हैं। इनकी तादाद पुरानी व्यवस्था की तुलना में कम है। इस नई प्रक्रिया को कर सुधार और कर वंचना रोकने की प्रणाली के नाम पर कर अधिकारियों के अधिकार संपन्न बनने के रूप में ही देखा जा सकता है। सरकार को जीएसटी के कामकाज को लेकर अपने बुनियादी अनुमानों की नए सिरे से जांच करनी होगी। यदि बड़े पैमाने पर कर वंचना हो रही है तो देखना होगा कि कहीं उसके डिजाइन में तो कमी नहीं है। ऐसे में अधिकारियों को चाहे जितने अधिकार सौंप दिए जाएं, दिक्कत दूर होने वाली नहीं है। सन 1990 और 2000 के दशक के विभिन्न कर सुधारों से बहुत पहले इंदिरा गांधी को यह सबक सीखने को मिल चुका था। खेद की बात है कि उस मोर्चे पर सरकार पीछे लौटती दिख रही है। ऐसा राजस्व में कमी की आशंका से हो रहा है।

पहले कदम में यह जांच होनी चाहिए कि क्या गिरफ्तारियों की व्यवस्था शुरू होने के बाद से रिकवरी में सुधार हुआ है। कितनी राशि वसूली जा सकी है? क्या गिरफ्तारी के हर मामले में अभियोजन शुरू किया गया? इसलिए कि यदि ऐसा नहीं किया गया तो क्या गिरफ्तार करना उचित था? अब वक्त आ गया है कि सरकार उस रास्ते से पीछे हटे जो भ्रष्टाचार और कानून के दुरुपयोग की ओर जाता है।

विनय सिन्हा

आर्थिक नीतियों के निर्माण में असली चमक पर हो जोर

अर्थव्यवस्था में सुस्ती दूर करने के लिए बजट की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखा जा रहा है। हालांकि सरकारी व्यय बढ़ाने का परंपरागत तरीका उतना कारगर नहीं रहेगा। बता रही हैं **प्रांजल भंडारी**

अर्थव्यवस्था के मुश्किल में फंसे होने से 1 फरवरी को आने वाले आम बजट की तरफ ध्यान कुछ अधिक ही केंद्रित हो रहा है। उम्मीद है कि सरकार व्यय मदों में तेजी लाएगी। लेकिन इतिहास पर नजर डालें और सहज बुद्धि से देखें तो यही लगता है कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए इस समय सरकारी व्यय बढ़ाने जैसे फौरी समाधान की जरूरत नहीं है।

भारत में तीन साल से बनी सुस्ती के बारे में हमारा अध्ययन नीति-निर्माताओं के लिए कुछ अहम सबक देता है। पहली नजर में आकर्षक लगने वाले उच्च सार्वजनिक निवेश और बढ़े हुए विदेशी मुद्रा भंडार जैसी बातों में भी कुछ नकारात्मक चीजें छिपी हो सकती हैं।

संकेत के तौर पर हम 2017 और 2018 में दिखी शुरुआती आर्थिक सुस्ती पर नजर डालते हुए इसकी शुरुआत कर सकते हैं। पांच वर्षों तक रही गिरावट के बाद निवेश में आई तेजी इस दौर की पहचान रही। इस निवेश वृद्धि में काफी योगदान सार्वजनिक क्षेत्र का था।

सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में सार्वजनिक निवेश का अंशदान वर्ष 2016 के 0.1 फीसदी से बढ़कर 2017 में 0.8 फीसदी हो गया। लेकिन सार्वजनिक व्यय में यह तेजी भी प्रच्छन्न लागत के बगैर नहीं थी। इस दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की उधारी बढ़ी जिसके तीन अनचाहे नतीजे सामने आए।

पहला, बचत उस हिसाब से नहीं बढ़ी जिस अनुपात में निवेश वृद्धि हुई। इसका परिणाम यह हुआ कि बचत और निवेश के बीच का फर्क गिर गया। यह उपाय देश के बाह्य चालू खाता संतुलन से कुछ ज्यादा नहीं है और घरेलू बचत के नाकाफी होने पर बाह्य फंडिंग पर निर्भरता बढ़ गई। इस दो वर्षों में चालू खाता घाटा तेजी से बढ़ गया।

दूसरा, बचत में लचर वृद्धि का समूची अर्थव्यवस्था के लिए ब्याज दरों पर प्रभाव पड़ा। भारत में लागू लगभग सभी ब्याज दरें उसी समय बढ़नी शुरू हो गईं।

तीसरा, सार्वजनिक निवेश बढ़ाने के पीछे आर्थिक वृद्धि तेज करने की सोच थी लेकिन यह गिर गई। जीडीपी उपभोग, निवेश और शुद्ध निर्यात का कुल जोड़ होता है लिहाजा निवेश बढ़ने पर शुद्ध निर्यात गिर गया।

यह पहलू बजट के लिहाज से एक अहम सबक देता है। यह मान लेना लुभावना है कि आर्थिक वृद्धि फिर से तेज करने के लिए सुस्ती के दौरान राजकोषीय घाटा बढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन घरेलू बचत नाकाफी होने की सूरत में यह ब्याज दरों पर दबाव और बाह्य वित्त पर तनाव डाल सकता है जिससे आर्थिक वृद्धि पर असर पड़ सकता है।

संक्षेप में, एक विशाल राजकोषीय संवर्द्धन पर आधारित कोई वृद्धि बहाली नीति उलटी भी पड़ सकती है। इससे अर्थव्यवस्था को मदद मिलने के बजाय प्रतिकूल असर पड़ेगा। यहां पर संतुलन यही होगा कि संसद द्वारा निर्धारित नए राजकोषीय नियमों से ही बंधा रहा जाए जो जीडीपी में 0.5 फीसदी फिसलन की ही अनुमति देते हैं। इससे कमजोर वृद्धि के चलते राजस्व में आने वाली कमी से निपटने की गुंजाइश बनेगी।

वृद्धि सुस्त पड़ने के मामले में 2019 में चुनौती 2017 और 2018 से काफी अलग थी। भारत की निवेश दर में वृद्धि का सिलसिला कायम नहीं रहा और बचत से बेमेल को दूर किया गया। इसका मतलब यह होना चाहिए था कि अर्थव्यवस्था में ब्याज दरें स्थिर या गिरावट पर हैं लेकिन असल में इसका उलटा हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने ब्याज दरों में 135 आधार अंकों की कटौती की लेकिन इसका उधारी दरों पर शायद ही असर पड़ा। पूरे साल अर्थव्यवस्था में ब्याज दर फैलाव बढ़ गया। इससे कुछ इतर भी गलत हो रहा था।

गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (एनबीएफसी) में 2018 के उत्तरार्द्ध में संकट गहराने के बाद उनकी बैलेंस शीट की सेहत को लेकर चिंता दिख रही थी। भारत के बैंक एनबीएफसी कंपनियों के लिए प्रमुख कर्जदाता रहे हैं लेकिन अचानक ही वे बांटे गए कर्जों की गुणवत्ता को लेकर सशंकित हो गए जिसका परिणाम यह हुआ कि वे जोखिम से काफी परहेज करने लगे।

वृहद-अर्थव्यवस्था के लिए इसका क्या मतलब है? तीन बातें खास हैं। पहला, बैंक अब कर्ज बांटने को उतने तैयार नहीं थे। निवेश के लिए उपलब्ध पूल भी सिकुड़ गया।

दूसरा, ब्याज दरों के ऊंचा होने से बचतकर्ता अधिक बचत करने को तरजीह दे सकते हैं। ऐसी स्थिति में बचत बढ़ती है और इससे चालू खाता घाटा भी बढ़ता है। ऐसे में क्या करना चाहिए? निवेश में गिरावट से आयात भी गिरता है जिससे व्यापार संतुलन में सुधार होता है। वास्तव में, चालू खाता घाटा वर्ष 2018 में जीडीपी के 2.1 फीसदी से गिरते हुए सितंबर 2019 में महज 0.9 फीसदी रह गया।

तीसरा, जब बैंक उधारी देने में हिचकने लगते हैं तो अधिक मात्रा में बचत विदेश जाने लगती है। इसे दुरुस्त करने का क्या तरीका है? आयात गिरने पर चालू खाता संतुलन में सुधार होता है और गिरावट के समय रुपये में तेजी नहीं चाहने से आरबीआई डॉलर खरीदने लगता है और अपने विदेशी मुद्रा भंडार में जमा करता है। यह भंडार आखिरकार अमेरिकी ट्रेजरी बिल जैसी अंतरराष्ट्रीय परिसंपत्तियों में निवेश किया जाता है।

संक्षेप में कहें तो बैंकों के स्तर पर जोखिम से बचने की कवायद घरेलू निवेश को कम कर सकती है जिससे देश की घरेलू बचत विदेश का रुख कर लेगी। सवाल है कि बजट के लिए इसके निहितार्थ क्या हैं?

हमारा मत है कि बजट सरकार को बैंकिंग प्रणाली में जोखिम वंचना कम करने और ऋण वृद्धि में जान फूंकने के लिए कदम उठाने का मौका देता है। असल में, हमारी राय में यह राष्ट्रीय नीति की प्राथमिकता होनी चाहिए क्योंकि इससे घरेलू बचत को देश में ही रखने और निवेश के लिए फंड जुटाने एवं आर्थिक वृद्धि बहाल करने में मदद मिलेगी।

इस मकसद को हासिल करने के लिए दिवालिया प्रक्रिया को मजबूत करना, रुके हुए निवेश को निर्बाध करना और सार्वजनिक बैंकों पर लागू सरकारी बाध्यताओं में कमी लाने जैसे कदम उठाने होंगे। एनबीएफसी की नियमन व्यवस्था में आमूलचूल बदलाव और रणनीतिक विनिवेश की रफ्तार तेज करने से भी मदद मिलेगी। असल में, बचत स्थिर होने से कुछ राजकोषीय समझदारी दिखाना और बैंकों के स्तर पर जोखिम वंचना दूर करने के कदम आर्थिक वृद्धि को बहाल करने के लिए सुनहरा मौका हो सकते हैं।

(लेखिका एचएसबीसी सिक्योरिटीज ऐंड कैपिटल मार्केट्स इंडिया की मुख्य अर्थशास्त्री हैं)

एयर इंडिया का स्वदेशी निजीकरण का मामला

दिल्ली डायरी

ए के भट्टाचार्य

केंद्र सरकार ने सोमवार को सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया में अपनी शत प्रतिशत हिस्सेदारी बिक्री के लिए शुरुआती बोलियां आमंत्रित करने का फैसला किया। इससे कई सवाल उठते हैं और देश की आर्थिक नीति के लिए उनके असर को समझना जरूरी है। एयर इंडिया में शेयरों की बिक्री के लिए जारी प्रारंभिक सूचना (पीआईएम) निजीकरण के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। लेकिन एयर इंडिया के निजीकरण के लिए मोदी ने कौन सा तरीका चुना है?

यह गलत धारणा है कि मोदी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) द्वारा इस मुद्दे पर उठाए गए संदेह और सवालों के बीच एयर इंडिया के निजीकरण का फैसला करके एक साहसिक कदम उठाया है। आरएसएस ने हमेशा एयर इंडिया के निजीकरण का विरोध किया है। लेकिन यह विरोध बेहद मामूली है।

उसका मुख्य विरोध इस बात को लेकर रहा है कि देश की राष्ट्रीय विमानन कंपनी को किसी विदेशी मालिक के हाथों नहीं सौंपा जाना चाहिए। खबरों के मुताबिक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक जनसभा में कहा कि एयर इंडिया में 49 फीसदी से अधिक हिस्सेदारी किसी विदेशी कंपनी के हाथ में नहीं दी जानी चाहिए। जर्मनी ने भी अपनी राष्ट्रीय विमानन कंपनी में 49 फीसदी से अधिक विदेशी हिस्सेदारी की अनुमति नहीं दी थी।

अब एयर इंडिया के निजीकरण के लिए जारी पीआईएम और नागरिक उड्डयन क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) नीति पर करीबी नजर डालते हैं। विदेशी कंपनियां या विदेशी निवेशक एयर इंडिया में केवल 49 फीसदी तक ही निवेश कर सकते हैं। एयर इंडिया का पर्याप्त स्वामित्व और प्रभावी नियंत्रण हमेशा भारतीयों के हाथों में रहेगा। यह नीति जनवरी 2018 में घोषित की गई थी। हालांकि इस शर्त में ढील देने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने पिछले बजट भाषण में घोषणा की थी कि सरकार उड्डयन, मीडिया (एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स) और बीमा क्षेत्रों को एफडीआई के लिए खोलने के वास्ते सभी संबंधित पक्षों से सुझाव लेगी। इनमें से उड्डयन को बाकी सभी क्षेत्रों के लिए एफडीआई नीतियों में पिछले कुछ महीनों में जरूरी संशोधन किए गए हैं।

मोदी सरकार का संदेश साफ है। उसे एयर इंडिया का निजीकरण तब तक स्वीकार्य है जब तक कि इसका नियंत्रण किसी विदेशी कंपनी के हाथों में नहीं जाता है। 2018 में एयर इंडिया के विनिवेश की कोशिश नाकाम रही थी लेकिन अब पीआईएम में कई तरह की छूट दी गई हैं। पहले 76 फीसदी हिस्सेदारी बेचने की बात थी और अब इसे शत प्रतिशत कर दिया गया है। पहले पात्र बोलीदाता के लिए नेटवर्थ 5,000 करोड़ रुपये रखी गई थी जिसे अब घटाकर 3,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है। पहले अधिग्रहणकर्ता के लिए बोली के शुरुआती चरण में लॉक-इन पीरियड तीन साल रखा गया था जिसे अब केवल एक वर्ष कर दिया गया है। पहले बोली जीतने वाली कंपनी को अपने कारोबार का एयर इंडिया के साथ विलय करने की अनुमति नहीं थी लेकिन अब इसकी अनुमति दी गई है। लेकिन एयर इंडिया पर एफडीआई नीति में कोई छूट नहीं दी गई है।

यह सरकार की आर्थिक नीति पर आरएसएस का प्रभाव है। मोदी सरकार ने एयर इंडिया के स्वामित्व पर आरएसएस के इस दृष्टिकोण को स्वीकार किया है कि कंपनी का स्वामित्व किसी विदेशी नागरिक को नहीं सौंपा जाना चाहिए। इसलिए निजीकरण स्वीकार्य है और एयर इंडिया का स्वामित्व बदल सकता है। लेकिन इसका प्रबंधन और स्वामित्व नियंत्रण हमेशा किसी भारतीय कंपनी या भारतीय नागरिक के हाथों में रहेगा। निजीकरण के बाद भी एयर इंडिया में किसी विदेशी संस्था या विदेशी विमानन कंपनी की केवल 49 फीसदी तक हिस्सेदारी हो सकती है। प्रबंधन नियंत्रण के बिना कौन सी विदेशी कंपनी एयर इंडिया में निवेश के लिए सहमत होगी? यह विदेशी विमानन कंपनी को ना कहने का अलग तरीका है। यह एक तरह का स्वदेशी निजीकरण है जहां नया निजी मालिक हमेशा एक भारतीय होगा। इस तरह के निजीकरण से सरकारी खजाने पर चपत लगेगी क्योंकि एयर इंडिया को खरीदने की होड़ सीमित होगी। इससे सरकार को इस सरकारी विमानन कंपनी में शत प्रतिशत हिस्सेदारी की बिक्री से कम राशि मिलेगी। अगर विदेशी निवेशकों को भी बहुलांश हिस्सेदारी के खरीदने के लिए समान अवसर दिया जाता तो सरकार को ज्यादा कीमत मिलती।

आदर्श स्थिति में द्विपक्षीय उड़ान अधिकार केंद्र सरकार के पास रहने चाहिए। सरकारी कंपनी के तौर पर एयर इंडिया का अस्तित्व खत्म होने के बाद इन्हें सरकार को लौटाया जाना चाहिए। यह फैसला करने का अधिकार सरकार को होना चाहिए कि ये अधिकार किसे मिलने चाहिए।

जो भी कंपनी एयर इंडिया को खरीदेगी, वह इन आकर्षक उड़ान अधिकारों को अपने पास रखना चाहेगी। लगता है कि सरकार एयर इंडिया के निजीकरण के बाद भी द्विपक्षीय उड़ान अधिकारों को एयर इंडिया के पास ही रखना चाहती है। शायद यही सोचकर सरकार ने एयर इंडिया के दरवाजे विदेशी विमानन कंपनियों के लिए बंद कर दिए। वह एयर इंडिया का स्वामित्व और प्रबंधन नियंत्रण उन्हें नहीं देना चाहती है।

संभव है कि प्रारंभिक दौर की बोली के बाद इन मुद्दों पर फैसला हो जाए। नागरिक विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने साफ किया है कि सरकार बाद में चरण में भी एयर इंडिया की बिक्री की शर्तों में बदलाव को तैयार है। सभी बोलीदाता शायद ही इस तरह की संभावना के लिए तैयार होंगे। बोली सौंपे जाने के बाद शर्तों में संशोधन की संभावना से अनिश्चितता बढ़ेगी और इसमें विवाद पैदा हो सकता है। इस तरह के विवाद से एयर इंडिया की बिक्री में मुश्किलें पैदा होंगी।

कानाफूसी

जागी अंतरात्मा

मध्य प्रदेश में भाजपा के बागी विधायक नारायण त्रिपाठी के दिमाग में क्या चल रहा है यह केवल वही जानते हैं। सर्वप्रथम उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा में एक विधेयक पर मत विभाजन के दौरान कमल नाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के पक्ष में मतदान किया। उस वक्त उन्होंने कहा कि वह ऐसा अपनी अंतरात्मा की आवाज पर कर रहे हैं। जब लोगों को लग रहा था कि वह पाला बदल चुके हैं तभी वह वरिष्ठ भाजपा नेता नरोत्तम मिश्र के साथ भोपाल के भाजपा मुख्यालय में अवतरित हुए और उन्होंने कहा कि वह अब भी अपनी पार्टी में ही हैं। बहरहाल, मंगलवार को एक बार फिर वह दूसरे पाले में नजर आए। उन्होंने नागरिकता अधिनियम 2019 का विरोध करते हुए कहा कि हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं लेकिन यदि हम लोगों को धर्म के आधार पर बांटेंगे तो देश नहीं चल पाएगा। कहा जा सकता है कि उनकी अंतरात्मा एक बार फिर जाग उठी है।

पेंटिंग के जरिये विरोध

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पिछले दिनों एक बार फिर कूची उठाई। इस बार उन्होंने ऐसा नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) और प्रस्तावित राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के विरोध में किया। वह एक ऐसे समूह में शामिल थीं जिसने कोलकाता की मेयो रोड पर महात्मा गांधी की मूर्ति के पास विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया था। उनके साथ कुछ अन्य कलाकार थे। ममता ने वहां मौजूद लोगों से कहा कि वे नागरिकता कानून का विरोध शांतिपूर्ण ढंग से करें। उन्होंने यह भी दोहराया कि वह प्रदेश में कभी भी इस कानून को लागू नहीं होने देंगी। उन्होंने कहा कि पेंटिंग सीएए और एनआरसी के खिलाफ जागरूकता फैलाने का एक जरिया हैं और इन्हें देश की विभिन्न दीर्घाओं में प्रदर्शित किया जाएगा।

ममता बनर्जी

आपका पक्ष

अर्थव्यवस्था के लिए प्रत्यक्ष कर संहिता

ऐतिहासिक कालक्रम में जब से अर्थव्यवस्था ने आकार लेना आरंभ किया है तभी से कर-व्यवस्था एक महत्त्वपूर्ण विषय रहा है। आरंभिक दौर से लंबे समय तक इसका आधार कृषि रहा है। लेकिन औद्योगिक क्रांति के पश्चात धीरे-धीरे कृषि का योगदान सिमटता चला गया और उसकी क्षतिपूर्ति विनिर्माण और सेवा क्षेत्र ने की। आज के दौर में ये दोनों ही कारक विश्व की तमाम अर्थव्यवस्थाओं के निर्धारक तत्त्व बने हुए हैं और भारत भी इससे अछूता नहीं है। प्रत्येक शासनकाल में कर व्यवस्था को लेकर मूल चिंता यही रही कि आखिर इसका स्वरूप क्या हो, दर का निर्धारण कैसे हो, कितनी दर रखी जाए और फिर वसूली का तरीका सख्त हो या नरम आदि। इन तमाम सवालों के जवाब खोजना आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि इनकी उत्पत्ति के दौर में था। गौरतलब है कि वर्ष 2017 में जीएसटी के रूप में अप्रत्यक्ष कर सुधार की ओर कदम बढ़ाया गया।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 जनवरी को बजट के लिए हलवा रस्म पूरी की

लेकिन अभी तक अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हो सके हैं। अब प्रत्यक्ष कर में सुधार का वक्त आ चुका है। इसके लिए प्रत्यक्ष कर संहिता के निर्माण की बात लंबे समय से चल रही है, लेकिन अभी तक इसे मूर्त रूप प्रदान नहीं किया जा सका है। प्रत्यक्ष कर संहिता वास्तव में प्रत्यक्ष कर-व्यवस्था को विनियमित करने के लिए मौजूदा कानूनों का सरलीकृत रूप होगा। अगर प्रत्यक्ष कर संहिता आकार लेती है तो यह आयकर अधिनियम 1961 व संपत्ति अधिनियम 1957 को विस्थापित कर देगी। सवाल यह उठता है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल, वर्तमान प्रत्यक्ष कर व्यवस्था को विनियमित करने वाले आयकर अधिनियम 1961 में विभिन्न संशोधनों के जरिये अनेक प्रावधान जोड़े-हटाए गए। इससे करदाता कर बचाने में सफल हो जाते हैं। इसके अलावा प्रावधानों की अतिव्याप्तता के कारण ही कालाधन, कर-चोरी, कर-आतंक जैसी समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। अगर इस में इसे लागू की जाती है तो यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए संजीवनी का कार्य कर सकती है। यह व्यक्तिगत करदाताओं को लाभान्वित करेगा बल्कि कॉरपोरेट घरानों, निवेशकों आदि पर भी सकारात्मक असर डालेगा। कर व्यवस्था को अधिकाधिक डिजिटल बनाया जाएगा। सरकार को इसके लाभ के साथ उपस्थित चुनौतियों को भी समय रहते दूर कर लेना चाहिए।

द्विजेंद्र कौशिक, अलवर

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in उस जगह का उल्लेख अवश्य करें, जहां से आप ईमेल कर रहे हैं।

कैसे आएगा वसंत

वसंत पंचमी के त्योहार में माता सरस्वती की पूजा की जाती है। इस धार्मिक परंपरा के साथ वसंत का संबंध प्रकृति से भी है। पतझड़ के बाद जब वसंत ऋतु आती है तब वृक्षों पर नए पत्ते आने लगते हैं। वसंत ऋतु में हर तरफ हरियाली का आगाज हो जाता है। लेकिन जैसे-जैसे मनुष्य ने प्रकृति से खिलवाड़ करना शुरू किया है, वैसे ही देश में हरियाली कम होती जा रही है। अगर इसी तरह कंक्रीट के जंगल बढ़ते गए तो वसंत पंचमी में देखने के लिए हरियाली नहीं रहेगी। वसंत पंचमी के बाद प्रकृति जो खूबसूरत नजारा वृक्षों के जरिये धरती पर बिखेरती है उससे धरती वंचित हो जाएगी। अगर आने वाली पीढ़ी को भारत के त्योहार जो कि प्रकृति से संबंधित है, उनका ज्ञान कराना है तो उसके लिए प्रकृति का संरक्षण बहुत जरूरी है। अगर प्रकृति हरी-भरी नहीं होगी तो वसंत का मौसम भी कैसे आएगा। अत: वसंत पंचमी पर सब यह प्रण लें कि हर हाल में प्रकृति को बचाना है।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

वायरस का औद्योगिक जिंसों पर असर

कोरोना वायरस के कारण चीन में नव वर्ष अवकाश बढ़ाने, शहरों को बंद किए जाने से मांग घटी

दिलीप कुमार झा
मुंबई, 29 जनवरी

चीन में कोरोना वायरस के फैलने और नव वर्ष के अवकाश को बढ़ाने से विश्व की इस दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में माल और लोगों की आवाजाही रुक जाने के कारण मांग घटी है, जिससे पिछले दो सप्ताह से भी कम समय में औद्योगिक जिंसों की कीमतें 9 फीसदी तक घटी हैं। सबसे ज्यादा गिरावट तांबे, कच्चे तेल और रबर में आई है।

कोरोना वायरस का फैलाव पहली बार 17 जनवरी को सुर्खियों में आया था। तब से बेंचमार्क लंदन मेटल एक्सचेंज (एलएमई) पर तांबा 9 फीसदी, निकल 8 फीसदी और जस्ता 6.7 फीसदी टूट चुका है। इस अवधि में कच्चे तेल के दाम 9 फीसदी लुढ़ककर 59.3 डॉलर प्रति बैरल पर आ गए हैं। वैश्विक बाजारों में 17 जनवरी से प्राकृतिक गैस और रबर के दाम क्रमश: 3.4 फीसदी और 7.7 फीसदी गिरे हैं।

सभी औद्योगिक जिंसों में कारोबारी रुझान कमजोर है। इसकी वजह यह है कि चीन के करीब आधा दर्जन शहरों में घातक कोरोना वायरस फैलने से नव वर्ष का अवकाश 2 फरवरी तक बढ़ा दिया गया है। चीन के ये शहर पश्चिम एशिया के बाजारों से जुड़े हुए हैं। चीन की सरकार ने इन शहरों को देश के शेष हिस्सों से व्यापार और लोगों की आवाजाही के लिहाज से बिल्कुल काट दिया है, जिससे तैयार उत्पादों की आपूर्ति और औद्योगिक जिंसों की मांग कमजोर पड़ी है।

> चीन पूरे विश्व में मूल धातुओं एवं रबर का दूसरा सबसे बड़ा और कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है, जिसे कोरोना वायरस के कारण तगड़ा झटका लगा है

कॉमट्रेंड्ज के निदेशक ज्ञानशेखर त्यागराजन ने कहा, 'औद्योगिक जिंसों की कीमतों में गिरावट की एकमात्र वजह चीन में कोरोना वायरस फैलने से मांग घटना है। चीन की सरकार ने कोरोना वायरस के फैलाव को नियंत्रित करने के लिए तत्काल कदम उठाए हैं, जिसे देखते हुए मध्यम अवधि में औद्योगिक जिंसों की कीमतों में फिर से उछाल आने की संभावना है। इसके साथ ही नए वर्ष के अवकाश के बाद चीनी कारोबारियों के कारोबारी गतिविधियां फिर शुरू करने से औद्योगिक जिंसों की मांग में धीरे-धीरे सुधार आने लगेगा।'

चीन पूरे विश्व में मूल धातुओं एवं रबर का दूसरा सबसे बड़ा और कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है, जिसे महामारी का रूप ले चुके कोरोना वायरस से तगड़ा झटका लगा है। चीन में लूनर नए वर्ष को मनाने के लिए एक सप्ताह का अवकाश घोषित किया गया था और देश में अवकाश की इस अवधि के बाद खरीद शुरू होने की संभावना थी। लेकिन दुर्भाग्य से इस वायरस के हमले से चीन और दुनियाभर के देश खौफजदा हैं।

रिलायंस कमोडिटीज के प्रमुख (जिंस) प्रीतम पटनायक ने कहा, 'शहरों में माल और लोगों की आवाजाही रोकी गई है, पर्यटन पर प्रतिबंध लगाए गए हैं, औद्योगिक और खुदरा खरीद लगभग थम गई है। यहां तक कि त्योहारी खरीद भी बुरी तरह प्रभावित हुई है क्योंकि चीन से जाने और आने वाले पर्यटकों पर रोक लग गई है। इससे रबर, कच्चे तेल और मूल धातुओं की कीमतों में गिरावट आई है। हालांकि मंगलवार को मामूली सुधार आया, लेकिन जिंसों की मांग और कीमतों पर वायरस के हमले का असर तब तक बना रहेगा, जब तक चीन इस महामारी से नहीं उबरता है।'

इस बीच औद्योगिक जिंसों में लंबी अवधि की संभावनाएं काफी अस्थिर हैं। इस साल अमेरिका में राष्ट्रपति चुनावों के कारण कैलेंडर वर्ष 2020 की पहली छमाही में जिंसों में तेजी और दूसरी छमाही में नरमी के आसार हैं। वैश्विक शेयर बाजारों की कोरोना वायरस के फैलने को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया रही है। पिछले दो सप्ताह में प्रमुख वैश्विक सूचकांक गिरे हैं। औद्योगिक उत्पादन की धीमी वृद्धि के कारण चांदी के दाम घटे हैं, जबकि सोना एक सीमित दायरे में बना रहा है।

औद्योगिक जिंस की कीमत

वस्तु	28 जनवरी	अंतर
ब्रेंट क्रूड (डॉलर प्रति बैरल)	59.3	-9.0
तांबा (डॉलर प्रति टन)	5,715	-8.9
निकल (डॉलर प्रति टन)	12,740	-7.9
टोक्यो रबर फ्यूचर (डॉलर प्रति किलो)	1.47	-7.7
जस्ता (डॉलर प्रति टन)	2,270	-6.7
प्राकृतिक गैस (डॉलर प्रति एमएमबीटीयू)	1.93	-3.4
चांदी (डॉलर प्रति ओंस)	17.5	-3.2
एल्युमीनियम (डॉलर प्रति टन)	1,745	-2.9
सोना (डॉलर प्रति ओंस)	1,567	0.6

अंतर 17 जनवरी से, स्रोत- ब्लूमबर्ग, संकलन- बीएस रिसर्च

इस साल 50 करोड़ टन का स्तर पार करेगी सीमेंट की स्थापित क्षमता!

अभिषेक रक्षित
कोलकाता, 29 जनवरी

मांग के कमजोर परिदृश्य के बीच इस साल देश में सीमेंट की कुल स्थापित क्षमता 50 करोड़ टन का स्तर पार जाने की उम्मीद है क्योंकि अल्ट्राटेक, जेके सीमेंट और डालमिया भारत समेत कई कंपनियां सालाना उत्पादन क्षमता में 2.3 करोड़ टन का इजाफा करने के अंतिम चरण में हैं। फिलहाल स्थापित क्षमता 48.5 करोड़ टन सालाना है और नई क्षमता वृद्धि से यह वर्ष 2020 में बढ़कर 50.8 करोड़ टन सालाना हो जाएगी।

सालाना उत्पादन क्षमता में जेके सीमेंट 42 लाख टन, अल्ट्राटेक 40 लाख टन और डालमिया भारत 35 लाख टन जोड़ेगी। रैमको सीमेंट 21 लाख टन क्षमता जोड़ेगी तथा अहमदाबाद स्थित सांघी इंडस्ट्रीज 20 लाख टन तथा मेघालय स्थित स्टार सीमेंट भी 20 लाख टन क्षमता वृद्धि कर सकती हैं। बिड़ला कॉरपोरेशन, वंडर सीमेंट और अंबुजा सीमेंट 52 लाख टन क्षमता विस्तार करेंगी।

हालांकि कमजोर मांग और नई क्षमता वृद्धि से दामों में और गिरावट आने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन येस सिक्योरिटीज के विश्लेषक कुणाल शाह का मानना है कि 31 दिसंबर, 2019 को समाप्त तीसरी तिमाही सीमेंट कंपनियों के लिए मजबूत साबित होगी क्योंकि आमदनी में सुधार की उम्मीद की जा रही है।

शाह ने कहा कि पूरे उद्योग में बिक्री वृद्धि के स्थिर रुख, पिछले साल के मुकाबले अच्छे दाम और कच्चे माल की लागत में नरमी से इसका संकेत मिल रहा है। इसके अलावा हमें कंपनियों की आमदनी में विषमता रहने के आसार लग रहे हैं क्योंकि इसमें क्षेत्रीय प्रभावों का असर रहेगा।

उद्योग के अधिकारियों का अनुमान है कि जिन कंपनियों का उत्तर और मध्य क्षेत्र में संपर्क है, वे अन्य क्षेत्रों की कंपनियों की तुलना में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगी। अब तक यह अनुमान लगाया गया है कि औसत दामों में क्रमबद्ध रूप से लगभग 3.5 प्रतिशत तक का इजाफा हो चुका है। उत्तरी, पश्चिमी और पूर्वी भारत में दामों में प्रति कट्टा 20 रुपये तक का इजाफा हुआ है, जबकि मध्य क्षेत्र में दामों में 10 रुपये तक का इजाफा हुआ है। हालांकि दक्षिण भारत में नवंबर के बाद से दामों में नरमी का रुख रहा है। शाह ने कहा कि इस साल नई क्षमता जुड़ने से पूर्वी भारत जैसे बाजारों में अत्यधिक दबाव की संभावना के कारण दामों में गिरावट आ सकती है।

हालांकि उम्मीद की जा रही है कि उत्पादन लागत के कारण तीसरी तिमाही के दौरान सालाना आधार पर शुद्ध आय में प्रति टन 1.6 प्रतिशत का इजाफा होगा। मांग में नरमी वाले हालात की वजह से औसत क्षमता उपयोग 70 प्रतिशत के स्तर पर रहा और इस वर्ष नई क्षमता आने से यह समान स्तर पर रहने की उम्मीद है।

बिड़ला कॉरपोरेशन के मुख्य परिचालन अधिकारी संदीप घोष ने कहा है कि सीमेंट क्षमता में हमेशा मांग की संभावना से इजाफा होता है। यह मानने का कोई कारण नहीं है कि ग्रामीण क्षेत्र में निवेश और केंद्र द्वारा वित्तीय मसले हल किए जाने के बाद परियोजनाएं शुरू होने से बुनियादी ढांचे में मांग जोर नहीं पकड़ेगी। केंद्र की प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) जैसी परियोजनाओं के साथ-साथ देश के कई हिस्सों में बेहतर फसल की वजह से व्यक्तिगत आवास खंड भी जोर पकड़ेगा।

सालाना उत्पादन

कंपनी	वृद्धि
जेके सीमेंट	42
अल्ट्राटेक	40
डालमिया भारत	35
रैमको सीमेंट	21
वंडर सीमेंट	20
सांघी इंडस्ट्रीज	20
स्टार सीमेंट	20
अंबुजा सीमेंट	18
बिड़ला कॉरपोरेशन	12

स्रोत : येस सिक्योरिटीज

अंतरराष्ट्रीय और घरेलू भाव

As on Jan 29	International Price	International %Chg#	Domestic Price	Domestic %Chg#
METALS ($/tonne)				
Aluminium	1,744.5	0.4	2,020.8	5.3
Copper	5,715.0	-2.8	6,286.8	2.9
Nickel	12,740.0	-23.6	13,471.8	-22.4
Lead	1,915.0	-15.5	2,161.1	1.4
Tin	16,345.0	-2.3	17,330.9	-1.8
Zinc	2,270.0	-12.2	2,540.0	-5.8
Gold ($/ounce)	1,571.3*	5.6	1,759.1	5.0
Silver ($/ounce)	17.5*	-1.7	19.9	-1.3
ENERGY				
Crude Oil ($/bbl)	59.1*	-3.0	59.0	-3.4
Natural Gas ($/mmBtu)	1.9*	-26.5	1.9	-29.6
AGRI COMMODITIES ($/tonne)				
Wheat	198.2	10.4	291.2	-4.1
Maize	186.7*	2.8	273.1	-2.8
Sugar	413.9*	22.3	487.4	-1.8
Palm oil	690.0	20.5	1,178.8	28.5
Rubber	1,469.4*	6.0	1,908.5	9.9
Coffee Robusta	1,315.0*	5.1	1,775.2	-7.2
Cotton	1,560.4	9.4	1,602.3	-1.0

* As on Jan 29, 20 1800 hrs IST, # Change Over 3 Months, Conversion rate 1 USD = 71.3& 1 Ounce = 31.1032316 grams.

Notes:
1) International metals, Indian basket crude, Malaysia Palm oil, Wheat LIFFE and Coffee Karnataka robusta pertains to previous days price. 2) International metal are LME Spot prices and domestic metal are Mumbai local spot prices except for Steel.
3) International Crude oil is Brent crude and Domestic Crude oil is Indian basket. 4) International Natural gas is Nymex near month future & domestic natural gas is MCX near month futures. 5) International Wheat, White sugar & Coffee Robusta are LIFF E future prices of near month contract. 6) International Maize is MATIF near month future, Rubber is Tokyo-TOCOM near month future and Palm oil is Malaysia FOB spot price. 7) Domestic Wheat & Maize are NCDEX future prices of near month contract, Palm oil & Rubber are NCDEX spot prices. 8) Domestic Coffee is Karnataka robusta and Sugar is M30 Mumbai local spot price. 9) International cotton is Cotton no.2-NYBOT near month future & domestic cotton is MCX Future prices near month tures.

Bloomberg chartMaker — Compiled by BS Research Bureau

एमसीएक्स

Name	Tovr (₹ Cr)	OI(000)
Agri commodity		
Cotton	72.3	36134
Oil and Oilseeds	230.4	85552
Spices	0.7	9
Metal(Jan 28)		
Metal- non ferrous	6505.3	40502
Metal- precious	15800.0	468
Oil and gas(Jan 28)		
Gas	2689.0	49464
Oil	16257.9	2405

एनसीडीईएक्स

Name	Tovr (₹ Cr)	OI(000)
Agri commodity		
Cotton	206.2	126055
Grains	153.6	95480
Oil and Oilseeds	641.9	464845
Others	148.0	66305
Pulses	53.3	33715
Spices	45.5	22601

एमसीएक्स बढ़ा/घटा

Name (Maturity)	Close	Day*
Gainers (* % Change)		
Crude Palm Oil (Jan 31)	785.5	2.2
Copper (Jan 31)	437.6	1.1
Zinc Mini (Jan 31)	177.4	1.1
Cotton (Jan 31)	19410.0	1.0
Kapas (Apr 30)	1095.5	1.0
Lead (May 29)	152.1	1.0
Losers (* % Change)		
Silver (Mar 05)	45474.0	-3.3
Silver Micro (Feb 28)	45493.0	-3.3
Silver Mini (Feb 28)	45494.0	-3.3
Aluminium (May 29)	140.2	-1.6
Mentha Oil (Jan 31)	1197.7	-0.9
Gold Mini (Feb 05)	40200.0	-0.9

एनसीडीईएक्स बढ़ा/घटा

Name (Maturity)	Close	Day*
Gainers (* % Change)		
Ref Soy Oil-IDR-2016 (Feb 20)	861.8	1.9
Shankar Kapas-Rajkot (Apr 30)	1097.5	1.4
Soyabean Indore (Feb 20)	4066.0	0.8
Guar Seed 10 (Feb 20)	3998.0	0.7
GuarGum 5T-Jodhpur (Feb 20)	7117.0	0.4
Mustard Seed Rape Oil (Feb 20)	4190.0	0.3
Losers (* % Change)		
Coriander-Kota (Apr 20)	6526.0	-2.1
Turmeric Nizamabad (Mar 20)	6066.0	-1.6
Jeera Unjha (Mar 20)	14205.0	-1.0
CottonSeed Oil-Akola (Feb 20)	1840.0	-0.9
Chana-Bikaner (Mar 20)	4032.0	-0.7
CastorSeed New-Disa (Feb 20)	3982.0	-0.5

एमसीएक्स बढ़त/छूट

Name (Maturity)	Futures	Prem/Dis
Premium over spot price (In %)		
Cardamom Vandanmedu (Feb 14)	3969.0	3.2
Kapas Surendranagar (Feb 28)	1070.0	2.8
Alumini-Mumbai (Jan 31)	147.6	2.5
Copper Mum (Jan 31)	437.6	1.7
Cotton-Rajkot (Jan 31)	19410.0	1.4
Zinc Mumbai (May 29)	181.4	0.2
Discount over spot price (In %)		
Menthol Oil Chandaus (Jan 31)	1197.7	-10.2
Lead Min Mumbai (Jan 31)	147.1	-6.1
Lead Mum (May 29)	152.1	-3.0
Aluminium Mum (May 29)	140.2	-2.6
Zinc Mini Mumbai (Jan 31)	177.4	-2.0
Nickel Mumbai (Jan 31)	938.9	-1.9

एनसीडीईएक्स बढ़त/छूट

Name (Maturity)	Futures	Prem/Dis
Premium over spot price (In %)		
Bajra-Delhi (Feb 20)	1874.0	2.4
Turmeric Nizamabad (Mar 20)	6066.0	1.1
Moong-Merta City (Feb 20)	7809.0	0.7
Paddy-Basmati-Karnal (Feb 20)	3212.0	0.4
Maize-Sangli (Feb 20)	1946.0	0.0
Discount over spot price (In %)		
Barley Jaipur (Apr 20)	1715.0	-20.2
Jeera Unjha (Mar 20)	14205.0	-6.8
Soy Bean Indore (Feb 20)	4066.0	-2.9
Coriander-Kota (Apr 20)	6526.0	-2.4
Crude Palm Oil Kandl (Jan 31)	741.9	-1.7
Guar Gum 5 MT-Jodhpu (Feb 20)	7117.0	-1.2

कल का हाजिर भाव

औद्योगिक

Metals .....Mumbai
Aluminium utensil scrap /kg 108.....(108)
Aluminium ingots /kg 144.....(144)
Brass sheet cutting /kg 325.....(326)
Brass utensil scraps/kg 305.....(308)
Copper heavy scrap /kg 418.....(418)
Copper utensil scraps/kg 391.....(391)
Copper wire bar /kg 448.....(451)
Lead ingots /kg 154.....(154)
Nickel Cathodes /kg 960.....(965)
Tin slabs /kg 1235.....(1240)
Zinc slabs /kg 181.....(181)
Source:Bombay Metal Exchange

Cotton .....Mumbai
Bengal Deshi /Qtl 10236.....(10236)
DCH - 32 /Qtl 11360.....(11557)
Jaydhar /Qtl 9758.....(9758)
Shankar- 6 /Qtl 11135.....(11079)
Source:Cotton Association of India

Oil .....Mumbai
Castor FSG /10kg 863.....(860)
Castor Comm /10kg 853.....(850)
Ricebran oil/10kg 820.....(820)
Groundnut oil /10kg 1140.....(1140)
Linseed oil /10kg 935.....(950)
Karanji /10kg 800.....(800)
Palm oil /10kg 840.....(835)
Sunflower exp ref /10kg 875.....(880)
Sunflower oil exp /10kg 850.....(850)
Soyabean ref / 10kg 865.....(875)
Source:Bombay Commodity Exchange

सॉफ्ट

Sugar .....Mumbai
Mumbai M-30 /Qtl 3362-3585 .....(3372-3585)
Source:Bombay Sugar Merchants Association

ऊर्जा

Crude Brent-$/Barrel .....
NYSE Crude 54.01.....(53.48)
Brent Crude (UK) 59.34 .....(59.33)
Brent Crude (WTI) 53.48.....(53.48)
NYSE Natural Gas-$/Mmbtu 1.91 .....(1.93)
Furnace/ 180 Cst &/bbl 318.45.....(319.47)
Naptha spot /Rs/MT 45170.....(45170)
LSHS spot/ M.T. 36150.....(36150)
Furnace Oil spot/ K.L. 33950.....(33950)
Source:Petroleum Bazaar.com

सर्राफा

Gold .....Mumbai
Standard (99.50 Purity) /10 gms 40302.....(40493)
Pure (99.90 Purity) /10 gms 40464.....(40656)
Silver.999/ kg 45535.....(46695)
Source:India Bullion & Jewellers Association

@SPOT PRICE(MCX, NCDEX & ICEX)

Commodity	Unit	PClose	Price (₹.) Close
29 mm Cotton-Rajkot (N)	1 B	18883.60	19019.05
Alumini-Mumbai (M)	1 K	143.35	143.95
Bajra-Delhi (N)	1 Q	1930.00	1830.00
Bajra-Jaipur (N)	1 Q	1867.05	1886.25
Barley Jaipur (N)	1 Q	2153.35	2150.00
Cardamom-Vand. (I)	1 K	3867.00	3850.00
Castor Seed Disa (N)	1 Q	4091.30	4090.00
Castor Seed-Kadi (N)	X	4060.00	4055.00
Chana Bikaner (N)	1 Q	4131.65	4125.00
Chana Delhi (N)	1 Q	4340.70	4350.00
Chana-Akola (N)	X	4100.00	4087.50
Coriander-Gondal (N)	X	6411.00	6444.00
Coriander-Jaipur (N)	X	6600.00	6587.50
Coriander-Kota (N)	1 Q	6702.95	6686.25
Cotton Seed Oilck Ak (N)	1 Q	1966.45	1936.20
Cotton Seed Oilck Ka (N)	1 Q	1995.25	1967.90
Cotton-Kadi (N)	1 B	18923.40	19050.90
CPO-Kandla (M)	10 K	772.20	781.20
Crude Palm Oil Kandl (N)	10 K	741.55	755.00
Crude Palm Oil-KAKIN (N)	10 K	760.00	770.00
Diamond 0.3 - Surat (I)	1 CT	905.75	906.20
Diamond 0.5-Surat (I)	1 CT	1551.80	1547.10
Diamond 1-Surat (I)	1 CT	3455.60	3448.90
Gold Ahm (M)	10 G	40456.00	40312.00
Gold Guinea-Ahmedaba (M)	8 G	32495.00	32379.00
Gold Petal-Mumbai (M)	1 G	4064.00	4041.00
Guar Gum 5 MT-Jodhpu (N)	X	7271.45	7200.00
Guar Seed 10 MT-Jodh (N)	1 Q	3998.95	3965.90
Guarseed-Jodhpur (I)	1 Q	3975.00	3940.00
Gur Muzaffar Nagar (N)	40 K	1113.35	1107.40
Isabgulseed-Unjha (I)	1 K	104.25	103.35
Jeera Jodhpur-Jodhpu (N)	X	16050.00	15900.00
Jeera Unjha (N)	1 Q	15333.35	15233.35
Kachi Ghani Must Oil (N)	10 K	870.20	870.00
Kapas Kadi-Kadi (N)	X	1030.25	1032.45
Kapas-Rajkot (N)	X	1027.15	1035.20
Lead Mum (M)	1 K	152.30	156.70
Maize Kharif-Nizamab (N)	X	1920.00	1940.00
Maize Rabi-Gulabbagh (N)	1	2252.50	2260.00
Maize-Erode (N)	X	1947.20	1931.80
Maize-Feed/Ind- Gula (N)	1 Q	2252.50	2260.00
Maize-Feed/Ind-Delhi (N)	1 Q	2050.00	2030.00
Maize-Sangli (N)	X	1939.00	1945.85
Masoor Grain Bold In (N)	1 Q	4712.50	4725.00
Moong-Merta City (N)	1 Q	7781.25	7756.25
Mustardseed Alwar (N)	20 K	4334.00	4385.50
Nickel Mumbai (M)	1 K	959.10	957.20
Paddy-Basmati-Karnal (N)	X	3200.00	3200.00
Paddy-Basmati-Karnal (I)	1 Q	3225.00	3216.00
Pepper-Ernakulam (I)	1 K	335.40	335.40
Pepper-Kochi (N)	1 Q	33654.55	33854.55
R M Oil-Sriganganaga (N)	X	847.50	852.50
Rape mustards-Patan (I)	20 K	760.00	750.00
Rapeseed Must.Seed (N)	X	1910.55	1912.50
Raw Jute-Kolkatta (N)	X	5290.90	5318.35
RBD Palm Olein Kakin (N)	10 K	836.90	840.00
Ref Soya Oil Indore (N)	10 K	880.00	881.05
Ref Soya Oil Mum (N)	10 K	874.00	881.15
Ref Soya Oil Nagpur (N)	10 K	887.50	887.50
Rubber-Kochi (N)	1 Q	13600.00	13600.00
Rubber-Kochi/Ernak. (I)	1 Q	13600.00	13592.00
Silver M-Ahemdabad (M)	1 K	46573.00	45478.00
Soy Bean Indore (N)	1 Q	4140.00	4186.00
Soy Bean Kota (N)	1 Q	4141.00	4095.25
Soy Bean Nagpur (N)	1 Q	4201.60	4216.75
Soy Bean-Akola (N)	X	4141.00	4201.00
Soymeal Indore (N)	1 T	33500.00	33500.00
Soyoil-Indore (I)	10 K	881.00	881.60
Steel Long-Ghaziabad (I)	1 T	31970.00	31830.00
Steel Long-MGG (I)	1 T	32180.00	32090.00
Steel Long-Raipur (I)	1 T	29220.00	28950.00
Sugar M Delhi (N)	1 Q	3255.00	3252.50
Sugar M Grade-Kanpur (N)	1 Q	3390.50	3372.35
Sugar M Grade-Kolhap (N)	1 Q	3284.15	3281.00
Sugar M Kolkatta (N)	1 Q	3476.20	3461.90
Sugar M Muzaff (N)	1 Q	3289.25	3301.50
Sugar S-Kolhapur (N)	1 Q	3140.00	3140.00
Turmeric Nizamabad (N)	1 Q	6000.00	6000.00
Wheat Delhi (N)	1 Q	2203.35	2208.00
Wheat Kota (N)	1 Q	2183.90	2170.50
Wheat New Indore (N)	1 Q	2187.50	2192.50
Wheat New Kanpur (N)	1 Q	2112.50	2115.00
Wheat New-Rajkot (N)	1 Q	2200.00	2212.50
Yellow Peas Mum (N)	1 Q	5625.00	5650.00
Yellow Peas-Kanpur (N)	1 Q	5750.00	5712.50
Zinc Mumbai (M)	1 K	179.00	181.05

* as on Jan 28, 20

(M) MCX ,(N) NCDEX & (I) ICEX Spot prices

जिंस वायदा

Name Exchange (Units)

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
DAY SESSION				
दिवस सत्र (बुधवार)				
कृषि जिंस				
Cotton				
Cotton MCX(1 B)				
Jan 31	19250, 19450, 19250, 19410	455	45	4035
Feb 28	19570, 19740, 19570, 19690	4405	580	26781
Mar 31	19870, 20030, 19870, 19960	982	151	4460
Apr 30	20210, 20210, 20180, 20200	106	4	157
CottonSeed Oil-Akola NCDEX(1 Q)				
Feb 20	1862, 1875, 1811, 1840	59110	4045	63170
Mar 20	1883, 1902, 1839, 1866	28260	2224	42430
Apr 20	1913, 1931, 1867, 1892	5550	457	13500
May 20	1950, 1958, 1900, 1908	1940	153	3420
Kapas MCX(20 K)				
Apr 30	1088, 1097.5, 1088, 1095.5	624	122	692
Shankar Kapas-Rajkot NCDEX(20 Kg)				
Apr 30	1090, 1098.5, 1089.5, 1097.5	1390	839	3535
Grains				
Barley Jaipur NCDEX(1 Q)				
Apr 20	1749, 1749, 1707, 1715	60	5	2030
May 20	1715, 1715, 1715, 1715	100	1	1770
Guar Seed 10 NCDEX(1 Qtl)				
Feb 20	3980, 4018, 3966, 3998	24955	2709	68655
Mar 20	4026, 4064, 4010, 4042	13240	1554	22705
Apr 20	4080, 4100, 4060, 4100	70	12	200
Oil and Oilseeds				
CastorSeed New-Disa NCDEX(1 Qtl)				
Feb 20	4012, 4026, 3970, 3982	3260	317	17660
Mar 20	4032, 4042, 3986, 4000	2130	247	13245
Apr 20	4030, 4030, 4018, 4022	175	23	3405
Crude Palm Oil MCX(10 K)				
Jan 31	780, 790, 777.5, 785.5	3690	270	16370
Feb 28	759, 776, 759, 766.5	21390	1646	52370
Mar 31	768, 771, 757.2, 759	2150	177	16220
Apr 30	760, 764.6, 760, 762.8	70	7	350
Mentha Oil MCX(1 K)				
Jan 31	1200.3, 1200.3, 1195, 1197.7	0.72	2	12.96
Feb 28	1208.8, 1215.4, 1197.1, 1205	162	399	220.68
Mar 31	1224.6, 1224.6, 1216, 1220.8	2.16	4	4.68
Mustard Seed Rape Oil NCDEX(1 Q)				
Feb 20	4191, 4205, 4171, 4190	8270	677	10600
Apr 20	4218, 4220, 4177, 4191	5280	450	11460
May 20	4196, 4199, 4186, 4193	230	15	2970
Ref Soy Oil-IDR-2016 NCDEX(10 Kg)				
Feb 20	860.4, 870, 856.4, 861.8	20655	2590	43985
Mar 20	850, 858, 844.6, 848.4	12770	1692	42400
Apr 20	854.2, 856, 843.4, 845.8	870	133	4460
Soyabean Indore NCDEX(1 Q)				
Feb 20	4068, 4110, 4048, 4066	25665	3096	116265
Mar 20	4044, 4092, 4038, 4054	25450	3136	123305
Apr 20	4076, 4092, 4028, 4040	12860	1559	61740
May 20	4074, 4074, 4028, 4034	1715	264	13090
Jun 19	4092, 4092, 4052, 4052	40	7	160
Others				
GuarGum 5T-Jodhpur NCDEX(1 Qtl)				
Feb 20	7118, 7157, 7069, 7117	11245	1173	32010
Mar 20	7200, 7248, 7160, 7200	9340	872	34095
Apr 20	7318, 7318, 7270, 7299	95	19	200
Pulses				
Chana-Bikaner NCDEX(1 Qtl)				
Mar 20	4075, 4083, 4025, 4032	11050	820	23080
Apr 20	4055, 4055, 4015, 4022	1930	182	8320
May 20	4083, 4084, 4050, 4063	190	19	2260
Spices				
Cardamom MCX(1 K)				
Feb 14	4001, 4001, 3937, 3969	0.2	2	5.3
Mar 13	3912.4, 3999, 3911.2, 3957	1.6	14	3.3
Coriander-Kota NCDEX(1 Q)				
Apr 20	6651, 6698, 6513, 6526	2600	238	9170
May 20	6612, 6612, 6500, 6500	100	8	430
Jeera Unjha NCDEX(1 Q)				
Mar 20	14380, 14380, 14180, 14205	477	153	2187
Apr 20	14100, 14100, 13930, 13980	222	66	1389
Turmeric Nizamabad NCDEX(1 Q)				
Mar 20	6190, 6240, 6042, 6066	2220	387	4975
Apr 20	6090, 6150, 5964, 5974	690	119	4325
May 20	6004, 6004, 6004, 6004	5	1	125
धातु				
Metal- non ferrous				
Aluminium Mini MCX(1 K)				
Jan 31	148.25, 148.5, 145.4, 145.95	85	44	490
Feb 28	139.95, 140.75, 139.9, 140.4	2383	1676	4284
Mar 31	140.85, 141.15, 140.35, 140.9	97	87	184
Copper MCX(1 K)				
Jan 31	439.5, 439.5, 436, 436.3	95	14	675
Feb 28	434.4, 434.9, 431.05, 431.75	15595	4885	12355
Mar 31	434.6, 435, 432.15, 432.8	295	115	400
Lead MCX(1 K)				
May 29	151.5, 151.5, 150.25, 151.05	4	3	9
Lead Mini MCX(1 K)				
Jan 31	147.85, 147.85, 146, 146.95	2	2	460
Feb 28	148.9, 149.2, 148.05, 148.45	3960	2646	5439
Mar 31	149.15, 149.25, 148.8, 149.05	14	14	124
Nickel MCX(1 K)				
Jan 31	950.3, 950.4, 950, 950.2	4.5	3	177
Feb 28	938.2, 942.4, 932.1, 938.8	14259	8421	4332
Mar

संक्रमण का बढ़ा शक, घटेंगे पर्यटक

दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ देशों की बुकिंग 20 से 60 फीसदी तक घटी

काठमांडू के हवाईअड्डे पर बुधवार को मास्क लगाकर उतरे यात्री (पीटीआई)

कैसे हालात

- वायरस नियंत्रित न होने पर गर्मियों में दिखेगा असर
- थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया और हॉन्गकॉन्ग भारतीय पर्यटकों की पसंदीदा जगह
- बैंकॉक या बाली घूमने जाने वाले भारतीयों के लिए टूर पैकेज के दाम होंगे कम

अनीश फडणीस

दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों में घूमने के लिए यात्रा बुकिंग रद्द होने से ट्रैवल एजेंट चिंतित हैं। हालांकि इन देशों की स्थानीय सरकारों ने कोरोना वायरस को नियंत्रित करने की मुहिम तेज कर दी है।

एयर इंडिया और इंडिगो ने बुधवार को चीन के लिए अपनी उड़ानें स्थगित करने की घोषणा की। हालांकि चीन की यात्रा में बड़ा हिस्सा कारोबारी यात्राओं का है, लेकिन बड़ी तादाद में लोग सिंगापुर, थाईलैंड और मलेशिया घूमने के लिए जाते हैं। थाईलैंड में कोरोना वायरस के 14 मामलों की पुष्टि हो चुकी है, जो चीन के बाहर किसी देश में सबसे अधिक हैं। थाईलैंड ने टूर लीडर्स और गाइड की स्क्रीनिंग शुरू की है। इसने स्थानीय यात्रा कंपनियों से कहा है कि वे अपने ग्राहकों में वायरस के लक्षणों पर नजर रखें। सिंगापुर ने उन नए पर्यटकों के आने और जाने पर रोक लगाने का फैसला किया है, जिन्होंने पिछले 14 दिनों में कोरोना वायरस प्रभावित चीन के हुबेई क्षेत्र की यात्रा की है।

सरकारों की इन पहलों के बावजूद ग्राहकों का भरोसा कमजोर है। क्लियरट्रिप डॉट कॉम वरिष्ठ उपाध्यक्ष बालू रामचंद्रन ने कहा, 'कोरोना वायरस फैलने की खबरें आने के बाद भारत में दक्षिण-पूर्व एशिया के कुछ देशों की बुकिंग में 20 से 60 फीसदी गिरावट आई है। इसके अलावा चीन के लिए बुकिंग 59 फीसदी कम हो गई हैं। चीन के अलावा जिन स्थानों के लिए बुकिंग में भारी गिरावट आई है, उनमें हॉन्गकॉन्ग (57 फीसदी), इंडोनेशिया (31 फीसदी), सिंगापुर (28 फीसदी) आदि शामिल हैं। अब तक जापान और कोरिया की बुकिंग पर कोई असर नजर नहीं आया है।'

ट्रैवल एजेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के संयुक्त सचिव रजत बगारिया ने कहा, 'इस समय यात्रा का रुझान नकारात्मक है। ग्राहक बैंकॉक, हॉन्गकॉन्ग और मकाऊ जैसी जगहों के लिए बुकिंग कन्फर्म नहीं कर रहे हैं। हमें डर है कि अगर कुछ सप्ताह में वायरस के फैलाव पर रोक नहीं लगी तो गर्मियों में भी हमारा कारोबार प्रभावित हो सकता है।'

विमानन सलाहकार सीएपीए के मुताबिक वर्ष 2018 में भारतीयों के लिए घूमने की पसंदीदा 10 प्रमुख विदेशी जगहों में थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया और हॉन्गकॉन्ग शामिल थे। इन देशों के हवाई संपर्क में सुधार हुआ है और वहां के वीजा नियम भी आसान हैं, जिससे भारतीय लोगों के बीच इन स्थानों की मांग बढ़ती जा रही है।

ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की अध्यक्ष ज्योति मायल ने कहा, 'थाईलैंड की बुकिंग पहले ही काफी रद्द हो चुकी हैं। जिन लोगों के सर्दी और खांसी है, वे इस देश में जाने को लेकर और ज्यादा चिंतित हैं। हालांकि दक्षिण-पूर्व एशिया की यात्रा को रोकने के लिए कोई सलाह जारी नहीं की गई है, लेकिन ग्राहक फिक्रमंद हैं।' टूर ऑपरेटर थॉमस कुक ने कहा कि उसने दक्षिण-पूर्व एशिया में घूमने के लिए जाने वाले लोगों की तादाद में कोई गिरावट दर्ज नहीं की है। कंपनी ने कहा, 'ग्राहक चीन में कोरोना वायरस की स्थिति को लेकर चिंता जता रहे हैं पर दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों के लिए मांग पर कोई असर नहीं पड़ा है। हम इस क्षेत्र के बहुत से स्थलों के टूर करा रहे हैं। जापान और दक्षिण कोरिया के हमारे टूर की भारी मांग आ रही है।'

यात्रा कारोबार से जुड़े एक वर्ग का मानना है कि बैंकॉक या बाली घूमने जाने वाले भारतीयों के लिए टूर पैकेज के दाम कम हो सकते हैं क्योंकि कोरोना वायरस के फैलने से विश्व के सबसे बड़े यात्रा बाजार चीन से टूर को लेकर संदेह पैदा हो गया है।

एयर इंडिया, इंडिगो की चीन उड़ान रद्द

अनीश फडणीस

देश की प्रमुख विमानन कंपनियों एयर इंडिया और इंडिगो ने वैश्विक विमानन कंपनियों ब्रिटिश एयरवेज और लायन एयर के फैसले का अनुसरण करते हुए चीन आने-जाने वाली उड़ानों को अस्थायी रूप से रोकने की घोषणा की है। एयर इंडिया ने कहा कि मुंबई-दिल्ली-शांघाई की उड़ान को 31 जनवरी से 14 फरवरी तक के लिए रद्द कर दिया गया है। वहीं इंडिगो ने अपनी दिल्ली-चेंगदु और बेंगलूरु-हॉन्गकॉन्ग की उड़ान 1 फरवरी से 20 फरवरी तक के लिए रद्द कर दी है। हालांकि इंडिगो अपनी कोलकाता-ग्वांगझाऊ तक की उड़ान को जारी रखेगी। पिछले कुछ दिनों से चीन मार्ग वाले उड़ानों की बुकिंग में कमी आई है क्योंकि कारोबारियों ने अपनी यात्रा टाल दी है। बड़ी तादाद में ग्राहकों ने विमानन कंपनी की बुकिंग रद्द कराई है। इंडिगो ने एक बयान में कहा है कि कंपनी ने कोरोना वायरस की वजह से बनी स्थिति का पूरा जायजा लेने के बाद यह फैसला लिया है। इंडिगो ने एक बयान में कहा, 'ये सभी अस्थायी और एहतियात के तौर पर उठाए गए कदम हैं।

हम ऐसा मानते हैं कि इन कदमों से हमारे ग्राहकों को असुविधा होगी ऐसे में हमने इन यात्रियों की पूरी राशि लौटाने का फैसला किया है। हमने कोलकाता-ग्वांगझाऊ की उड़ान को जारी रखने का फैसला किया है जिसकी हम रोजाना आधार पर निगरानी कर रहे हैं।' दोनों विमान कंपनियों ने अपने पायलट और चालक दल को पूर्वी एशियाई देशों में उड़ानों का संचालन करते वक्त एहतियात बरतने का सुझाव दिया है। इंडिगो ने अपने पायलट और केबिन क्रू को मास्क पहनने और थाईलैंड, वियतनाम और सिंगापुर में ठहराव के वक्त सार्वजनिक जगहों पर न जाने की सलाह दी है।

चीन से विदेशियों की स्वदेश वापसी जारी

अमेरिका और जापान ने कोरोना वायरस के केंद्र बने चीन के एक शहर से अपने नागरिकों को निकाल लिया है और ब्रिटिश एयरवेज ने चीन आने-जाने वाली अपनी सभी उड़ानें रद्द कर दी हैं क्योंकि इस वायरस की चपेट में आने से 132 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ सरकारी अर्थशास्त्रियों ने अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगने की आशंका जताई है। चीन में इस वायरस से संक्रमित होने वालों की तादाद करीब 5,974 है।

चीन के हुबेई प्रांत इस संक्रमण का केंद्र रहा है जिसकी राजधानी वुहान है जहां के वन्यजीव बाजार में पिछले महीने यह वायरस फैला। चीन के राष्ट्रपति ने भी यह स्वीकारा की हालात गंभीर है। अमेरिका, फ्रांस और सिंगापुर सहित 15 अन्य देशों में इस वायरस संक्रमण के करीब 60 मामले सामने आएं हैं लेकिन इनमें से किसी की भी मौत नहीं हुई है। हालांकि संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आया है। पीड़ित व्यक्ति का परिवार वुहान से है। चीन के कई शहरों में सड़कें खाली दिखीं और जो चुनिंदा लोग नजर आए उन्होंने मास्क पहना हुआ था।

इस वायरस का दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ रहा है। कंपनियां चीन में यात्रा करने पर प्रतिबंध लगा रही हैं और विमानन कंपनियां चीन की उड़ानों में कटौती कर रही हैं। जुए का प्रमुख केंद्र मकाऊ लगभग भूतहे शहर में तब्दील हो चुका है जबकि मॉल और शॉपिंग केंद्र भी खाली-खाली ही दिखें। खनन क्षेत्र से लेकर लक्जरी वस्तुओं के क्षेत्र पर भारी असर दिख रहा है।

विभिन्न देशों के नागरिकों को देश से निकालने में सहयोग करेगा चीन

वृद्धि में कमी

चीन के एक सरकारी अर्थशास्त्री का कहना है कि इस वायरस से फैली महामारी का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि पर पड़ेगा और 2020 की पहली तिमाही में वृद्धि दर कम होकर 5 फीसदी या इससे कम पर सिमट सकती है। दरअसल इस संकट का कई अन्य क्षेत्रों पर साफ असर देखा जा रहा है। ऐसे में नीतिनिर्माताओं को ज्यादा राहत उपाय करने होंगे।

मदद का वादा

भारत ने चीन से हुबेई प्रांत से अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए दो उड़ानों की इजाजत देने का अनुरोध किया है। कोरोना वायरस के केंद्र चीन के वुहान से अपने नागरिकों को निकालने की भारत की तैयारियों के बीच चीन ने कहा कि अगर कोई देश अपने नागरिकों को निकालने पर जोर देता है तो सभी उचित प्रबंध किए जाएंगे और जरूरी मदद दी जाएगी।

ऑटो एक्सपो से बाहर नहीं चीनी कंपनियां: सायम

टी ई नरसिम्हन

चीन में कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे की वजह से मशहूर वाहन प्रदर्शनी 'ऑटो एक्सपो 2020' में चीन की कंपनियों की भागीदारी को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। वाहन कंपनियों के भारतीय संगठन (सायम) ने कहा है कि स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देशों के अनुरूप ही आयोजन स्थल पर पर्याप्त रूप से एहतियात बरता जा रहा है। बुधवार को सायम के प्रतिनिधियों ने स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात कर ऑटो एक्सपो के दौरान उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा की।

सायम के अध्यक्ष राजन वढेरा ने कहा, 'कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए सायम के प्रतिनिधि के तौर पर हमने बताया कि स्वास्थ्य मंत्रालय के सुझावों के अनुरूप ही ऑटो एक्सपो-दि मोटर शो के आयोजन स्थल पर पर्याप्त रूप से सतर्कता बरती जा रही है।'

सायम के अधिकारियों ने स्थानीय प्रशासन और अन्य सरकारी अधिकारियों के साथ बुधवार को नई दिल्ली में ऑटो एक्सपो से जुड़ी कई दौर की बैठकें कीं। सायम से जुड़े एक अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा, 'ऑटो एक्सपो में हिस्सा लेने वाली चीन की कंपनियों के प्रतिनिधि भारत में मौजूद हैं ऐसे में चीन से एक बड़े प्रतिनिधि मंडल के आए बिना भी ये कंपनियां इस आयोजन में हिस्सा ले सकती हैं।'

चीनी कंपनियों के प्रतिनिधि भारत में मौजूद

चीन की कंपनियों में ग्रेटवॉल भी शामिल है जो इस साल भारतीय बाजार में अपनी शुरुआत करेगी। इसके अलावा अन्य बड़ी चीनी कंपनियों में बीवाईडी और हाइमा शामिल हैं। सूत्रों का कहना है कि ग्रेटवॉल के अधिकारी करीब एक महीने पहले ही चीन से भारत आ चुके हैं और उन्हें एक्सपो में शिरकत करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चीन की कंपनी एसएआईसी भी देश में सक्रिय है और इसके उत्पाद देश के बाजार में उपलब्ध हैं। हालांकि इस आयोजन में हिस्सा लेने के लिए चीन से इसके अधिकारियों का आना मुश्किल लग रहा है।

बहुराष्ट्रीय कंपनियों का फरमान

फेसबुक ने अपने कर्मचारियों से कहा है कि वे जरूरी होने पर ही चीन की यात्रा करें और जो कर्मचारी चीन चले गए हैं वे घर से ही दफ्तर का काम करें। अलीबाबा ने अपने कर्मचारियों को कहा कि चीनी नववर्ष की छुट्टियों के एक हफ्ते बाद भी वे घर से काम कर सकते हैं। टेनसेंट ने अपनी छुट्टियां 9 फरवरी तक बढ़ा दी हैं। एचएसबीसी ने हॉन्गकॉन्ग और चीन की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है और वहां पहुंच चुके कर्मचारियों को घर से काम करने की सलाह दी है। गोल्डमैन सैक्स और स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने भी कर्मचारियों को घर से बाहर न निकलने की सलाह दी है। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने भी हुबेई प्रांत जाने वाले कर्मचारियों को 7 दिनों तक घर में रहने को कहा है। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स और एलजी केमिकल ने चीन तक की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है। होंडा और निसान ने अपने कर्मचारियों को एक सरकारी चार्टर्ड विमान के जरिये चीन से जापान वापस बुला लिया है। नोवार्तिस ने अपने कर्मचारियों से 10 फरवरी तक घर से काम करने को कहा है। फॉक्सवैगन ने चीन के कर्मचारियों को अतिरिक्त दो हफ्ते तक घर से काम करने की अनुमति दे दी है। *रॉयटर्स*

ममता-राज्यपाल में खींचतान

अभिषेक रक्षित

विपक्षी दल द्वारा शासित राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच राजनीतिक टकराव के आसार होते हैं। ऐसा होने के प्रबल आसार तब होते हैं, जब राज्य की मुख्यमंत्री तेजतर्रार नेता तथा केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार की कड़ी आलोचक ममता बनर्जी हों और राज्यपाल सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व वकील और भारतीय जनता पार्टी के पुराने समर्थक जगदीप धनखड़ हों।

केसरी नाथ त्रिपाठी का कार्यकाल खत्म होने और धनखड़ को जुलाई 2019 में राज्यपाल बनाए जाने के बाद राजनीतिक हलकों में मुख्यमंत्री और उनके के बीच देर-सबेर टकराव के आसार जताए जा रहे थे। इसकी शुरुआत पिछले साल जाधवपुर विश्वविद्यालय से हुई। उस समय छात्रों ने कथित रूप से केंद्रीय मंत्री बाबुल सप्रियो का घेराव किया और धनखड़ को संभवतया उन्हें बचाने के लिए विश्वविद्यालय जाना पड़ा। सुप्रियो आरएसएस की छात्रा शाखा एबीवीपी के निमंत्रण पर विश्वविद्यालय गए थे। यह घटना भाजपा बनाम वाम मोर्चे की राजनीतिक बहस बन सकती थी। लेकिन धनखड़ ने इसके लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में जो कुछ हुआ, उससे राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति का पता चलता है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और उनकी पार्टी- तृणमूल कांग्रेस की सरकार है।

तृणमूल कांग्रेस ने धनखड़ के पिछले राजनीतिक जुड़ाव को देखते हुए उन्हें हमेशा संदेह की नजर से देखा है। तृणमूल उनके शब्दों को स्वीकार करने के बजाय पलटवार किया है। पार्टी ने धनखड़ पर आरोप लगाया है कि राज्यपाल ने राज्य सरकार को भरोसे में न लेकर पक्षपाती भूमिका अदा की है। धनखड़ ने भाजपा बोली बोलते हुए बनर्जी पर राज्य में कानून-व्यवस्था न होने का आरोप लगाया है। इससे तृणमूल की भौहें तन गई हैं।

पिछले साल पूरे अक्टूबर महीने में एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप के बाद अब राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच यह आम हो गया है। एक अन्य मामल में राज्यपाल ने आरोप लगाया था कि राज्य सरकार ने उन्हें विधानसभा के अंदर जाने की मंजूरी नहीं दी। उन्होंने कहा कि स्पीकर को पहले सूचित करने के बाद भी दरवाजा बंद था।